सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कभी भी अपने अतीत से शर्मिंदा न हों क्योंकि आज आप जो कुछ भी हो, वो आपका हिस्सा है।

वर्ष 01, अंक 195, नई दिल्ली

बुधवार, 27 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली में अब आपके घर तक पहुंचाएगी ये 'छुटकू' बस, इसी साल शुरू हो जाएगी सुविधा

संजय बाटला, सम्पादक

दिल्ली में जल्द ही मोहल्ला बसें चलेंगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी रूट फाइनल करने किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना के तहत छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस स्कीम को लागू करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रूट फाइनल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वहीं इस योजना के तहत चलाने के लिए छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों से पता चला है कि 2080 बसों में से 1040 बसें खरीदने के लिए डीटीसी प्रबंधन इसी हफ्ते बस निर्माता कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। ये सभी 9 मीटर आकार वाली छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जो पूरी तरह एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होंगी। इन 1040 बसों से 728 बसें पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी से और 312 बसें जेबीएम ग्रुप से खरीदी जाएंगी। तीन महीने में इन बसों की डिलिवरी शुरू हो जाएगी।

योजना के तहत आएंगी 2080 बसें

सूत्रों ने बताया कि मोहल्ला बस योजना के तहत जो 2080 बसें आएंगी, उन्हें डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के तहत 50-50 की पार्टनरशिप में चलाया जाएगा। डीटीसी के लिए 1040 बसें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते साइन होने वाला है, वहीं क्लस्टर स्कीम के तहत चलने वाली 1040 बसों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट विभाग पहले ही इन्हीं दोनों कंपनियों के साथ साइन कर चुका है। ट्रांसपोर्ट विभाग को भी 728 बसें पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी से और 312 बसें जेबीएम ग्रुप से मिलेंगी। इन बसों की डिलिवरी अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक मोहल्ला बस योजना शुरू हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बसों की खरीद और डिलिवरी की प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, ताकि बसें मिलने में देरी न हो।

12 मीटर साइज वाली बसें भी आएंगी

इसके अलावा दिल्ली सरकार डिम्ट्स और डीटीसी के तहत चलाने के लिए अलग से 12 मीटर साइज वाली 1900 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीद रही है। इनमें से 50 प्रतिशत बसें अशोका लीलेंड कंपनी की इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली सहभागी स्विच मोबिलिटी से खरीदी जाएंगी, जबकि 30 प्रतिशत बसें पीएमआई इलेक्ट्रो से और 20 प्रतिशत बसें जेबीएम ग्रुप से खरीदी जाएंगी। स्विच मोबिलिटी के साथ पिछले हफ्ते ही ट्रांसपोर्ट विभाग ने 950 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। अगले 4 से 5 महीनों में चरणबद्ध तरीके से इन बसों की डिलिवरी भी मिल जाएगी। ये सभी बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल 800 इलेक्ट्रिक बसों की तरह होंगी और इनके आने के बाद क्लस्टर स्कीम के तहत भी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पीएम ई-बस सेवा योजना में चंडीगढ़: केंद्र से प्रति किमी मिलेगी 24 रुपये सब्सिडी

चंडीगढ़। वर्तमान में नौ मीटर की बस से सीटीयू को प्रति किमी करीब 35 रुपये की कमाई हो रही है। बताया जा रहा है अब जो बसें आएंगी वह 12 मीटर की होंगी, जिसमें बैठने और खड़े होने की क्षमता ज्यादा होगी। हालांकि, सीटीयू के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि आने वाली बसों से भी कम से कम प्रति किमी 35 रुपये की आमदनी तो होगी ही।

पिछले काफी समय से लोकल रूट पर घाटे में चल रहे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) के जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम ई-बस सेवा योजना में चंडीगढ़ का चयन हुआ है। इसमें सीटीयू को 100 बसों के लिए केंद्र सरकार से प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इन 100 बसों को छह महीने के अंदर सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में शहर की सड़कों पर जो 80 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, वे केंद्र सरकार की ओर से फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम इंडिया) योजना के अंतर्गत लाई गई हैं। प्रति बस केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी है लेकिन अब सब्सिडी देने के मॉडल को बदला जा रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बस संचालन के विस्तार के लिए केंद्र ने पीएम-ई बस सेवा को लांच किया है। इसमें चंडीगढ़ को शामिल किया है, जिसके तहत शहर को 100 ई-बसों के लिए प्रति बस 24 रुपये प्रति किलोमीटर की सब्सिडी मिलेगी।

बसों को खुद नहीं खरीद रहा सीटीयू

दरअसल, अब सीटीयू बसों को खुद खरीद नहीं रहा है बल्कि पीपीपी मोड पर कंपनियों से प्रति किमी पर समझौता कर रहा है। वर्तमान में 40-40 कर 80 ई-बसों के लिए दो कंपनियों से समझौता हुआ है। पहली 40 बसों के लिए अशोक लेलैंड से 10 साल के लिए 154.01 करोड़ और फरवरी 2022 में अन्य 40 बसों के लिए वॉल्वो-आयशर के साथ 10 साल के लिए 115.44 करोड़ रुपये में समझौता हुआ। वॉल्वो-आयशर को सीटीयू 44.99 रुपये प्रति किलोमीटर चुका रहा है। सीटीयू को सिर्फ किमी के अनुसार कंपनी को पैसे देने हैं, बस, ड्राइवर, बसों का रखरखाव, चार्जिंग स्टेशन आदि सब कुछ कंपनी की जिम्मेदारी होती है।

अब ऐसे लाभ में आ सकता है सीटीयू

वर्तमान में नौ मीटर की बस से सीटीयू को प्रति किमी करीब 35 रुपये की कमाई हो रही है। बताया जा रहा है अब जो बसें आएंगी वह 12 मीटर की होंगी, जिसमें बैठने और खड़े होने की क्षमता ज्यादा होगी। हालांकि, सीटीयू के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि आने वाली बसों से भी कम से कम प्रति किमी 35 रुपये की आमदनी तो होगी ही। इसके साथ ही केंद्र सरकार से प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। ऐसे में सीटीयू की आमदनी कुल 59 रुपये प्रति किमी की होगी और जिस भी कंपनी से बस चलाने के लिए समझौता होगा वह 45 रुपये के आसपास होगा।

दिल्ली से झज्जर तक ई-बसें चलाने की तैयारी
महिलाओं को मिल सकती है फ्री यात्रा की सौगात

झज्जर से दिल्ली के बीच जल्द ही अब डीटीसी की ई-बसें चलाए जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात का भरोसा दिलाया है। डीटीसी की बसों के चलने से झज्जर के कई गांव सीधे मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इससे एक और बड़ा फायदा होगा। महिलाओं को झज्जर से दिल्ली तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

चंडीगढ़। झज्जर से दिल्ली तक डीटीसी की ई-बसें चलाने की तैयारी है। अगर डीटीसी की बस सेवा शुरू हो जाती है तो झज्जर सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। साथ ही महिलाओं को झज्जर से दिल्ली तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में मंगलवार को डीटीसी बसें चलाने की मांग को लेकर पहुंचे झज्जर जिले के सरपंचों को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल खाप प्रधान 84 सुनील गुलिया, दरियापुर के सरपंच पवन, जहांगीरपुर के सरपंच सुखदेव, खीरी के सरपंच रामवीर और माजरी के सरपंच धर्मवीर ने कहा कि ई-बसें चलने से आवागमन आसान होगा।

मेट्रो से जुड़ेंगे कई गांव, हजारों लोगों को होगा फायदा

अनुराग ढांडा ने कहा कि झज्जर बस स्टैंड तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने पर जिले के गांव भी सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। झज्जर से हर रोज हजारों लोग नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए दिल्ली का सफर करते हैं। साथ ही झज्जर और आसपास के जिलों के हजारों लोग भी अच्छे और विश्वस्तरीय इलाज के लिए दिल्ली के सरकार के अस्पतालों का रूख करते हैं। दिल्ली से झज्जर शहर के बस स्टैंड तक बस सेवा शुरू होने पर हजारों लोगों का पैसा और समय भी बचेगा। झज्जर की हजारों महिलाएं भी फ्री सफर कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली नजफगढ़ टर्मिनल से एम्स-झज्जर (बाढ़सा गांव) के बीच दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस सेवाओं का विस्तार पहले ही किया जा चुका है। यह सेवाएं दिल्ली और हरियाणा के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले रोगियों और एम्स कर्मचारियों सहित हजारों

यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। डीटीसी बसें वर्तमान में दौराला सीमा के माध्यम से नजफगढ़ टर्मिनल और एम्स झज्जर के बीच चलती हैं।

भारत में कार निर्माता वाहन स्क्रैपिंग को दें बढ़ावा, नितिन गडकरी की अपील

गडकरी ने वाहन निर्माताओं से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए और अधिक निवेश लाने के साथ-साथ कार मालिकों को केंद्र की वाहन स्क्रैपिंग नीति के फायदों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर भारत में कार निर्माताओं से प्रदूषण को कम करने और खरीदारों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि पुराने वाहन स्क्रैपिंग सभी हितधारकों के लिए एक जीत की स्थिति प्रदान करती है क्योंकि इससे नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों को रीसाइक्लिंग करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने पहले वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 15-20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक व्यापक वाहन स्क्रैपिंग नीति लागू की थी।

पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए भारत में अभी भी पर्याप्त संख्या में वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स नहीं हैं। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे कार निर्माता पहले ही देश भर में अपनी वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स लॉन्च कर चुके हैं। गडकरी ने पहले कहा था कि कार निर्माताओं और डीलरों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। गडकरी ने वाहन निर्माताओं से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए और अधिक निवेश लाने के साथ-साथ कार मालिकों को केंद्र की वाहन स्क्रैपिंग नीति के फायदों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया है। मंत्री ने कहा, ₹ऑटो उद्योग इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, उन्हें आगे आना चाहिए और तीन मुख्य स्तंभों का समर्थन करना चाहिए।₹ उन्होंने कार निर्माताओं से देश भर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा था कि वाहन स्क्रैपिंग नीति से ऑटोमोबाइल की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ जाएगी। उनका मानना है कि कबाड़ हुए वाहनों से हासिल कच्चे माल का इस्तेमाल करने से कच्चे माल की खरीद पर 33 प्रतिशत लागत की बचत होगी और नए वाहनों की बिक्री में 18-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनका मानना है कि यह नीति भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग हब (विनिर्माण केंद्र) बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

अगस्त 2021 में पहली बार पेश की गई वाहन स्क्रैपिंग नीति, वाहन प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए पूरे भारत में पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर केंद्रित है। क्योंकि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करने के लिए जाने जाते हैं। इस नीति का मकसद 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द करना है।

एनएचएआई में प्रबंधक सहित कई पदों पर भर्तियां, दो लाख से अधिक मिलेगा वेतन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रबंधक, उप प्रबंधक, महाप्रबंधक और जूनियर हिंदी अनुवादक के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अक्तूबर 2023 तक है।

रिक्तियों का विवरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 62 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण निम्नलिखित है-

महाप्रबंधक (तकनीकी) 10 पद

उप महाप्रबंधक (तकनीकी) 20 पद

प्रबंधक (तकनीकी) 30 पद

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक 02 पद

शैक्षणिक योग्यता

एनएचएआई की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार को सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद में मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना जरूर पढ़ें।

2023 वेतनमान

महाप्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगाः लेवल -13 (रु. 123100-215900) / (पूर्व-संशोधित) पीबी -4 (रु. 37400-67000) और ग्रेड वेतन 8700 रुपये

उप महाप्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगाः लेवल -12 (रु. 78800-209200) / (पूर्व-संशोधित) पीबी -3 (रु. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 7600 रुपये

प्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगाः लेवल -11 (रु. 67700-208700) / (पूर्व-संशोधित) पीबी-3 (रु. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 6600 रुपये

महिलाएं इस बीमारी को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, 5 लक्षणों से पहचान कर इलाज जरूरी, डॉक्टर से समझें बचाव के तरीके

यूरिन इंफेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है. यूरिन इंफेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है.
यूरिन इंफेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है. यह एक तरह का ब्लैडर इंफेक्शन है, जो किडनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय को प्रभावित करता है. इस तरह का इंफेक्शन होने पर महिलाओं को काफी तकलीफ होती है. समय रहते उचित इलाज न होने पर इंफेक्शन पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है. आइए गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी से जानते हैं यूटीआई के लक्षणों के बारे में-

आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान महिलाओं पर भारी पड़ रहा है. इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या यूटीआई भी बड़ी समस्याओं में एक है. सामान्य भाषा में इसे यूरिन इंफेक्शन भी कहा जाता है. यह एक तरह का ब्लैडर इंफेक्शन है, जो किडनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय को प्रभावित करता है. इस तरह का इंफेक्शन होने पर महिलाओं को काफी तकलीफ होती है. इस परेशानी का एक बड़ा कारण यूटीआई के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना भी है. यही वजह है कि कई महिलाएं यूरिन इंफेक्शन के लक्षणों को नजरंदाज कर देती हैं. हालांकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि यह समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है. समय रहते उचित इलाज न होने पर इंफेक्शन पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है. आइए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली की गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी से जानते हैं यूटीआई के लक्षणों के बारे में-

महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन होने के 5 संकेत

पेट के निचले हिस्से में दर्द: महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. क्योंकि यह यूरिन इंफेक्शन होने का भी संकेत हो सकता है. इस तरह की दिक्कत होने पर दर्द के साथ जलन का भी अनुभव हो सकता है. बता दें कि, कई महिलाएं इसे पीरियड का दर्द समझ कर इग्नोर कर देती हैं. लेकिन ऐसा करना गलत है. इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है.

पेशाब में जलन: दर्द के साथ पेशाब में होने वाली जलन भी यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों में से एक है. इस बीमारी के होने पर पेशाब करते समय तेज जलन महसूस हो सकती है. इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन से बचने के लिए पब्लिक टॉयलेट यूज करते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

बार-बार पेशाब आना: महिलाओं में बार-बार पेशाब आना भी यूरिन इंफेक्शन का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, कई बार तेज पेशाब का प्रेशर महसूस तो होता है, लेकिन टॉयलेट जाने पर बहुत कम मात्रा में यूरिन पास होता है. यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो यूरिन टेस्ट करवाने के साथ चिकित्सीय सलाह जरूरी है.

अधिक थकान लगना: यूरिन इंफेक्शन का एक बड़ा संकेत हर वक्त थकान भी हो सकती है. ऐसे में यदि आपको भी बिना कोई काम किए ही हर समय थकान महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज करना गलत हो सकता है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए.

पेशाब का रंग बदलना: महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन होने पर कई बार पेशाब का रंग बदल जाता है, जो अक्सर पीला या मटमैले रंग का हो सकता है. कई बार यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि पेशाब से ब्लड भी निकलने लगता है. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं.

प्रेग्नेंसी में क्यों खाना चाहिए मखाना? किन परेशानियों से मिलती है निजात, जानें 1 दिन में कितने मखाने खाना सही

प्रेग्नेंसी के दौरान आपको डाइट में मखाने को जरूर शामिल करना चाहिए. इससे मां और पेट में पल रहा बच्चा दोनों हेल्दी रहेंगे.
दरअसल, मखाना पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में मखाने क्यों फायदेमंद हैं? किन परेशानियों को दूर करते हैं? दिनभर में कितने मखाना खाना सही? इन सवालों के बारे में बता रही हैं गायनोकॉलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा...

प्रेग्नेंसी हर महिला के लिए सबसे सुखद अहसास होता है. ऐसे में हर महिला की चाह होती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल और पेट में पल रहा शिशु हेल्दी हो. इसके लिए आपको डाइट में कुछ ड्राइफ्रूट्स को जरूर शामिल करना चाहिए. खासतौर पर मखाना. दरअसल, मखाना पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है. बेशक आप इसको कभी भी खा लें, लेकिन प्रेग्नेंसी में यह बेहद लाभकारी होता है. गर्भावस्था के दौरान मखाने खाने से प्रेग्नेंट महिला और उसके शिशु की सेहत को कई लाभ हो सकते हैं. अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में मखाने क्यों फायदेमंद हैं? किन परेशानियों को दूर करते हैं? दिनभर में कितने मखाना खाना सही? इन सवालों के बारे में विस्तार से बता रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनोकॉलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा

इन पोषक तत्वों का भंडार है मखाना

डॉ. साहा के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में मखाने का सेवन फायदेमंद होता है. दरअसल, मखाने में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी होते हैं. इसके अलावा मखाने में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए आप इसे स्नैक के रूप में खा सकती हैं. इससे मां के साथ पेट में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है.

दिनभर में कितने मखाना खाना सही

डॉ. साहा के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को मखाने खाना बेहद फायदेमंद है, लेकिन बहुत अधिक खाने से बचें. इसके लिए बेहतर होगा कि 1 दिन में एक से दो मुट्ठी ही मखाने खाएं. ऐसा करने से मां और शिशु दोनों हेल्दी रहेंगे.

प्रेग्नेंसी में मखाना खाने के 5 चमत्कारी लाभ

हड्डियां मजबूत होंगी: प्रेग्नेंसी में मखाने खाने से शरीर को मजबूती मिलती है. दरअसल, मखाना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है. ऐसे में ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है. प्रेग्नेंसी में मखाना खाने से गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद होने वाले हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है. इसके लिए यदि आप मखाने को घी में भूनकर खाती हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा.

खून की कमी सुधारे: मखाने का सेवन आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है. बता दें कि, प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है. ऐसे में यदि आप मखाना खाती हैं तो हीमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में आप शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर कर सकती हैं. इसका आप सीमित मात्रा में सेवन कर सकती हैं.

कब्ज से दिलाए राहत: प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है, जिससे निजात पाना बेहद जरूरी है. इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी डाइट में मखाने को शामिल कर सकती हैं. बता दें कि, मखाना फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके लिए आप मखाने को रोस्ट करके या दूध में उबालकर खा सकती हैं.

पितृपक्ष- श्राद्ध 2023

29 सितंबर 2023, शुक्रवार से 14 अक्टूबर 2023, शनिवार तक श्राद्ध पक्ष रहेगा।

सनातन धर्म- शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष रहता है।

पितृ पक्ष 2023 श्राद्ध की मुख्य तिथियां-:

पूर्णिमा श्राद्ध- 29 सितंबर
प्रतिपदा का श्राद्ध - 29 सितंबर
द्वितीया श्राद्ध तिथि- 30 सितंबर
तृतीया तिथि का श्राद्ध- 1 अक्टूबर
चतुर्थी तिथि श्राद्ध- 2 अक्टूबर
पंचमी तिथि श्राद्ध- 3 अक्टूबर
षष्ठी तिथि का श्राद्ध- 4 अक्टूबर
सप्तमी तिथि का श्राद्ध- 5 अक्टूबर
अष्टमी तिथि का श्राद्ध- 6 अक्टूबर
नवमी तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर
दशमी तिथि का श्राद्ध- 8 अक्टूबर
एकादशी तिथि का श्राद्ध- 9 अक्टूबर
माघ तिथि का श्राद्ध- 10 अक्टूबर
द्वादशी तिथि का श्राद्ध- 11 अक्टूबर
त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध- 12 अक्टूबर
चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध- 13 अक्टूबर
सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध तिथि- 14 अक्टूबर

मुख्यमंत्री ने उत्तरी ज़ोनल कौंसिल की बैठक में अमित शाह के आगे ज़ोरदार ढंग से उठाए पंजाब के मसले

(साहिल बेरी)

अमृतसर। पंजाब के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता अधीन हुई उत्तरी ज़ोनल कौंसिल की 31वीं बैठक में राज्य के अलग-अलग मुद्दों को ज़ोरदार ढंग से उठाया।

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और पंजाब के लोगों की केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का स्नेहपूर्ण स्वागत किया। उत्तरी ज़ोनल कौंसिल की 31वीं बैठक पवित्र शहर में करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र नगरी का समूची मानवता के दिलों में गहरा सम्मान है, जहाँ हर रोज़ एक लाख श्रद्धालु माथा टेक कर हरेक के भले के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अतीत में यह शहर कारोबारी सरगर्मियों का केंद्र रहा है और राज्य सरकार के प्रयासों के स्वरूप यह शहर जल्दी ही मध्य एशिया और उससे पार की मंडियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा।

मेहनती और बहादुर पंजाबियों ने पाँच नदियों की इस धरती पर इतिहास के कई पन्ने पलटते हुए देखे हैं। देश के अन्न भंडार के तौर पर नाम कमाने के साथ-साथ पंजाब को देश की खडग़भुजा होने का भी गर्व हासिल है और पंजाबियों को विश्व भर में अपनी बहादुरी, सहनशीलता और उद्यमी होने की भावना के कारण जाना जाता है। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि मेहनती पंजाबी, जो दुनिया भर में अपने उद्यमी कौशल, सहनशीलता और कुशलता के कारण जाने जाते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उत्तरी ज़ोनल कौंसिल हमारे आर्थिक विकास के लिए अंतरराज्यीय सहयोग के स्तर को बढ़ाने के लिए यह बहुत बढिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के हित में है कि हम एकसाथ बैठें और इस क्षेत्र, जो भौगोलिक तौर पर ज़मीनी हदों और सरहदों के साथ जुड़ा होने के कारण हमेशा नुकसान में रहा है, के सामाजिक-आर्थिक विकास की बेहतरीन संभावनाएं ढूँढें।

मुल्क में सही मायनों में संघीय ढांचे की ज़रूरत की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह बात महसूस की जा रही है कि राज्यों को और ज्यादा वित्तीय एवं राजनीतिक शक्ति दी जाएँ। उन्होंने कहा कि इस पक्ष पर सभी एकमत हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जंजाल से ऊपर उठकर राज्य सरकारों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के चयन और राजस्व के लिए काम करने के लिए ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, परन्तु बदकिस्मति से पिछले 75 सालों में इस अधिकार पर केंद्रीयकरण का रुझान हावी रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा, ''यह बात हर कोई जानता है कि आधुनिक युग में राज्य सरकारें अपने लोगों की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं।''

भाखड़ा ब्यास प्रशासनिक बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में राजस्थान को मैंबर नियुक्त करने की माँग पर ज़ोरदार विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य पुनर्गठन एक्ट 1966 के प्रस्तावों के अधीन बी.बी.एम.बी. का गठन हुआ और यह एक्ट मूलभूत रूप से दो उत्तराधिकारी राज्यों पंजाब और हरियाणा के मसलों के बारे में है। इस एक्ट के सभी प्रस्तावों के साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कारणों से वह भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से किसी तीसरे मैंबर को शामिल करने के प्रस्ताव का सख़्ती से विरोध करते हैं।

शानन पावर हाऊस प्रोजैक्ट का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने दुख से कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जोगिन्दरनगर में शानन पावर हाऊस को स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया गया है, जिसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि साल 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजैक्ट के लिए 99 सालों के लिए ज़मीन लीज़ पर दी थी, जिसकी समय-सीमा साल 2024 में ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि इस मुद्दे को उठाया गया जबकि यह प्रोजैक्ट पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के उपबंधों के अंतर्गत पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा गया था। पंजाब पुनर्गठन एक्ट संसद का एक्ट है जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बने। ज़िक्रयोग्य है कि इसी एक्ट ने नीचे की ओर बस्सी पावर हाऊस (उल हाइडल प्रोजैक्ट पड़ाव-2) की मलकीयत और कंट्रोल हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सौंपी है। यह स्थिति आधी सदी से अधिक समय से भारत सरकार द्वारा बिना कोई छेड़छाड़ के कायम रखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने साल 1975 से 1982 तक अपने खर्चे पर प्रोजैक्ट का विस्तार किया और इसकी क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि

यह मामला केंद्रीय बिजली मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद अभिव्यक्त की कि भारत सरकार उपरोक्त और सही कानूनी स्थिति बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि शानन पावर हाऊस की मलकीयत के सम्बन्ध में लिया गया कोई भी अन्य स्टैंड एक्ट के उलट होगा और पंजाब एवं इसके लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइन्साफ़ी होगी।

बी.बी.एम.बी. में सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पदों पर सीधे तौर पर खुली भर्ती द्वारा भरने के कदम की सख़्त विरोधता की। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी, 2022 को बी.बी.एम.बी. (संशोधन) नियम केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए थे, जिसके मुताबिक सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पद खुली भर्ती के द्वारा सीधे तौर पर भरे जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने इसकी विरोधता करते हुए कहा कि इन नये नियमों ने पुरानी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके मुताबिक मैंबर ऊर्जा हमेशा पंजाब से नियुक्त होता था, जबकि मैंबर सिंचाई हरियाणा से नियुक्त होता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी व्यवस्था में पंजाब से कोई भी इंजीनियर मैंबर ऊर्जा के पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि साल 2022 से पहली व्यवस्था बहाल की जाए क्योंकि बी.बी.एम.बी में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि बी.बी.एम.बी. का गठन भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के अंतर्गत हुआ था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की कि वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को बी.बी.एम.बी का पक्का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को हिदायत दें क्योंकि यह संस्था चेयरमैन और सदस्यों की पक्की नियुक्ति की अनुपस्थिति में अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंप कर चलाई जा रही है।

राजस्थान द्वारा भाखड़ा डैम और पौंग डैम में जल भंडार का स्तर बरकरार रखने की की जा रही माँग के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी तौर पर जब यह दोनों डैमों का डिज़ाइन तैयार किया गया था तो उस समय पर भाखड़ा डैम की असली ऊँचाई 1685 फुट थी और पौंग डैम की ऊँचाई 1400 फुट थी। उन्होंने कहा कि साल 1988 के समय के दौरान पंजाब ने कई बार बाढ़ का सामना किया और उसके बाद भारत सरकार और सी.डब्ल्यू.सी. ने एक फ़ैसला लिया और भाखड़ा एवं पौंग डैमों का एफ.आर.एल. का स्तर क्रमवार 5 फुट और 10 फुट घटा दिया गया था। यहाँ यह भी बताने योग्य है कि सतलुज या ब्यास नदियों का बाढ़ का पानी हरियाणा या राजस्थान या किसी अन्य राज्य को नहीं जाता। इस कारण पंजाब को साल 1988 में, साल 2019 में, इस समय के दरमियान और हाल ही में कुछ पहले पंजाब को बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जब राजस्थान से संकट के समय में पंजाब सरकार को कोई सहयोग नहीं मिलता तो डैमों के पूरे जल भंडार के स्तर को बढ़ाना अनुचित है।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा 15 मई, 2023 को अपने पत्र के द्वारा, बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन को हिमाचल प्रदेश द्वारा जल सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए पानी निकालने के बारे में एन.ओ.सी. सर्टिफिकेट लेने की शर्तों में ढील देने के जारी किए गए निर्देशों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी. को जारी किए गए निर्देश, पंजाब राज्य को स्वीकार नहीं हैं और भारत सरकार द्वारा इस पर फिर विचार किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि जल समझौतों के मद्देनज़र, सतलुज और ब्यास नदी में से हिमाचल प्रदेश राज्य को पानी का वितरण करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. का काम रोपड़, हरीके और फ़िरोज़पुर में डैम, जल भंडारों, नंगल हाइडल चैनल और सिंचाई हैड्डवर्कस का केवल प्रबंधन, रख-रखाव और संचालन करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अधीन बी.बी.एम.बी. को नदियों में से पानी हिस्सेदार राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य को देने का अधिकार नहीं है और हिमाचल प्रदेश तो हिस्सेदार राज्य भी नहीं है।

ऑपरेशन में युवक के पेट से निकला 500 ग्राम का तौलिया, हर्निया की सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने छोड़ा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजधानी के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक युवक के पेट में 500 ग्राम का तौलिया छोड़ दिया। ऑपरेशन वाले हिस्से में दोबारा दर्द होने पर वह लोक नायक अस्पताल दिखाने पुहंचा जहां पर ऑपरेशन वाली जगह से 500 ग्राम वजनी तौलिया निकला। अब विवाद निवारण आयोग ने पीड़ित के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया है।

दिल्ली। ऑपरेशन करते वक्त पेट में तौलिया छोड़ने के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार मानते हुए उत्तर पूर्वी जिला विवाद निवारण आयोग ने पीड़ित के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया है। साथ ही इसी मामले से जुड़े दिल्ली मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट में पाया कि डॉक्टर ने गैर पंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन किया था।

यह देखते हुए आयोग ने डॉक्टर को आदेश दिया है कि वह मुआवजा राशि शिकायत की तिथि से भुगतान होने तक छह प्रतिशत ब्याज सहित दे। दवा, परामर्श शुल्क और आने-जाने पर हुए खर्च के लिए 50 हजार रुपये और विधिक खर्च के लिए 25 हजार रुपये ब्याज समेत पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है।

हर्निया में गांठ व सूजन की आई दिक्कत

पुरानी सीमापुरी निवासी अनवर अहमद ने आयोग में शिकायत की थी। उसके मुताबिक, 12 मार्च 2016 को उनके पेट में दर्द हुआ था। उसके उपचार के लिए वह यमुना विहार सी-4 स्थित समरा अस्पताल गए थे। वहां पर डॉ. अब्दुल खालिक और डॉ. अब्दुल कादिर ने देखने के बाद जांचें कराई थीं। उसमें हर्निया में गांठ व सूजन की समस्या सामने आई थी।

उस पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। 22 मार्च 2016 को इस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। तीन दिन बाद छुट्टी मिलने पर रुपये भुगतान कर घर चले गए थे। घर पहुंचने के बाद ऑपरेशन वाले हिस्से में दर्द होने लगा था और पस के साथ पानी निकलने लगा था। 26 मार्च 2016 को फिर से अस्पताल जाकर डॉ. अब्दुल कादिर को दिखाया था।

ऑपरेशन वाली जगह से निकला तौलिया

इसके बाद भी कई चक्कर लगाए, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। फिर वह लोक नायक अस्पताल दिखाने पुहंचे। वहां नियमित पट्टी के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। इस पर 31 अगस्त 2016 को उनकी सर्जरी की गई, जिसमें पहले ऑपरेशन वाली जगह से 500 ग्राम वजनी तौलिया निकला। सर्जरी के अगले दिन यहां से उनको छुट्टी दे दी गई थी।

इस शिकायत में अनवर ने समरा अस्पताल, डॉ. अब्दुल खालिक और डॉ. अब्दुल कादिर को प्रतिवादी बनाया था। आयोग में डॉ. अब्दुल खालिक ने अपने और अस्पताल की तरफ से लिखित पक्ष दाखिल किया था कि शिकायत झूठी है, उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं थी। इंग्विनल मेश के साथ हर्नियोप्लास्टी की गई थी।

मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने का आदेश

आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता संक्रमण के लिए खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि वह नियमित रूप से पट्टी कराने नहीं आए थे। मेश निकालने के लिए उनको निःशुल्क ऑपरेशन कराने का मौका भी दिया गया था।

इस प्रकरण में लोक नायक अस्पताल ने पक्ष रखते हुए बताया कि अनवर के पेट से पहले ऑपरेशन वाली जगह से तौलिया निकला था।

वहीं, इस मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट में पाया कि वो ऑपरेशन गैर पंजीकृत अस्पताल में किया गया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता को परेशानी हुई थी। इस पर आयोग के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाले कोरम ने डॉ. अब्दुल खालिक की लापरवाही मानी और उनको आदेश दिया कि वह पीड़ित को मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा राशि का भुगतान करें।

टूलकिट मामले में जमानत शर्त में संशोधन से जुड़ी दिशा रवि की याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज

वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

नई दिल्ली। वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। रवि की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने रवि को 13 फरवरी 2021 को किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत देते समय निचली अदालत ने दिशा रवि पर कई शर्तें लगाई थीं। इसमें यह भी कहा था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी। दिशा रवि ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें इतनी छूट जाए कि विदेश जाने से पहले वह निचली अदालत को सूचित करेंगी।

ज्वेलरी शोरूम में करीब 25 करोड़ रुपये की चोरी, स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर गहने उड़ा ले गए चोर

दिल्ली के जंगपुरा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर धावा बोलते हुए करोड़ों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलते ही निजामुद्दीन थाने पुलिस ने मौके पर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि टीम को शक है कि चोरी रविवार रात को हुई है। चोर शोरूम की दीवार काटकर अंदर घुसे थे।

नई दिल्ली। दिल्ली के जंगपुरा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर धावा बोलते हुए करोड़ों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलते ही निजामुद्दीन थाने पुलिस ने मौके पर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि भोगल इलाके में जिस आभूषण की दुकान में चोरी हुई मेंटीम को शक है कि चोरी रविवार रात को हुई है। चोर शोरूम की दीवार काटकर अंदर घुसे थे, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे करोड़ों को गहने चुरा लिए।

पुलिस के हाथ लगा CCTV फुटेज

डीसीपी साउथ-ईस्ट राजेश देव ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है। उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ये चोरी के एक बड़ी घटना है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराधियों को दुकान और आभूषणों के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्हें पता था कि स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचना है। उन्होंने बताया कि चोरों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में भी जानकारी थी। जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी पहले से ही अपनी योजना बनाने के लिए वहां आये थे।

दुकान में थे 20-25 करोड़ के आभूषण: मालिक

ज्वेलरी शोरूम के मालिक संजीव जैन नें एएनआई से बात करते हुए बताया, 'हमने रविवार को दुकान बंद कर दी थी और सोमवार की छुट्टी के बाद जब हमने इसे मंगलवार को खोला तो हमने देखा कि पूरी दुकान में धूल भरी हुई थी और स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार में एक छेद था... हमें लगता है कि चोरों ने सब कुछ लूट लिया है। करीब 20-25 करोड़ रुपये की ज्वेलरी थी। चोर दुकान के अंदर छत के रास्ते से दाखिल हुए थे। सीसीटीवी समेत सबकुछ टूटा हुआ है।'

शरजील इमाम की जमानत अर्जी स्थगित, अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दिल्ली दंगे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सोमवार को आरोपित शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर तय की है। मामले में बताए गए अपराध के तहत अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि वह न्यायिक हिरासत में बिता चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सोमवार को आरोपित शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर निर्णय नहीं हो सका। अब इस मामले में कोर्ट अगले महीने यानी 13 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा। शरजील ने सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत यह कहते हुए वैधानिक जमानत अर्जी लगाई थी कि इस मामले में बताए गए अपराध के तहत अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि वह न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। इस पर सोमवार को अभियोजन की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कोर्ट में कहा कि वह सीआरपीसी की इस धारा के संबंध में संसदीय बहस रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं।

साथ ही अर्जी पर अपना लिखित पक्ष देना चाहते हैं। इस मौके पर कोर्ट ने केस में राजद्रोह के आरोप की धारा लगाने के संबंध में प्रश्न पूछा। इस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस के लिए समय मांग लिया गया। कोर्ट ने फिर अगली तारीख तय कर दी।

घर जलाने के प्रयास के मामले में दो पर आरोप तय

वहीं, दिल्ली दंगे के दौरान चोरी व घर जलाने का प्रयास करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दो लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जबकि इसमें शामिल दुकानें जलाने के संबंध में तीन लोगों की शिकायतें फिर से जांच के लिए दयालपुर थाने के एसएचओ को भेज दी गई हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रत्येक शिकायत की ठीक से जांच करके उसे तार्किक निष्कर्ष पर लेकर जाना पुलिस का कर्तव्य है। दयालपुर थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी एन्क्लेव में 24 फरवरी 2020 की शाम साढ़े चार बजे दंगाइयों ने छिद्दा लाल तोमर के घर में लूटपाट की थी, साथ आग लगाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में प्राथमिकी की गई थी। इसमें 11 शिकायतें और जोड़ दी गई थीं। जांच के दौरान समय और स्थान अलग होने पर इनमें से आठ शिकायतों को इस केस से वापस ले लिया गया था। केवल घर जलाने के प्रयास और दुकानें जलाने की चार शिकायतों पर जांच आगे चली। इसमें पुराना मुस्तफाबाद निवासी फिरोज खान उर्फ पप्पू और मोहम्मद अनवर को आरोपित बनाया गया। आरोपों के बिंदुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने छिद्दा लाल तोमर के घर में आग लगाने के प्रयास की घटना को लेकर दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

SC ने दिल्ली HC के फैसले को बदलने से किया इनकार, विधि कोर्सों में एडमिशन से जुड़ा है मामला

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सामान्य विधि परीक्षा स्नातक (क्लैट-यूजी) के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इनकार कर दिया।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सामान्य विधि परीक्षा स्नातक (क्लैट-यूजी) के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने विधि पाठ्यक्रमों में कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के अंकों के आधार पर प्रवेश देने के लिए निर्देश देने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, हम अब इस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है, जहां उसने इस वर्ष के लिए क्लैट के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी है। यह अनुचित आदेश नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा व जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्य सभी विश्वविद्यालयों में इस शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं अंतरिम आदेश पारित किया था।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को डीयू को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए क्लैट-यूजी के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति दी थी।

दिल्ली से झांसी जा रही ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, फिर जो हुआ; रह जाएंगे दंग

24 सितंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते-होते बच गया। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर नई दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया। तो आरपीएफ के जवान एएसआई घनश्याम मीना ने दौड़ कर ट्रेन के साथ घसीटते हुए यात्री को सुरक्षित बचाया।

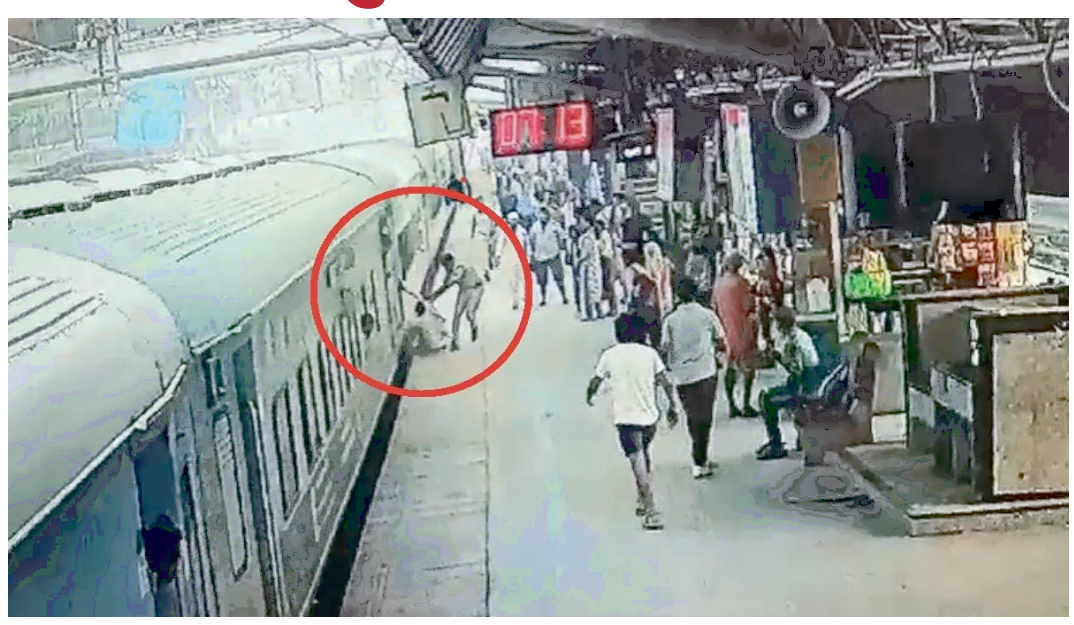

नई दिल्ली। 24 सितंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते-होते बच गया। नई दिल्ली से झांसी जाने वाली ताज एक्सप्रेस में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर आई और जैसे ही रवाना हुई तो एक यात्री का चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में पैर फिसल गया।

यात्री का पैर ट्रेन ओर प्लेटफार्म के बीच मे जाने लगा तो आरपीएफ के जवान एएसआई घनश्याम मीना ने दौड़ कर ट्रेन के साथ घसीटते हुए यात्री को पकड़ा। किसी तरह से यात्री को ट्रेन ओर प्लेटफार्म के बीच जाने से सुरक्षित बचा लिया।

सुरक्षित बचाया गया यात्री उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में डुमरई का रहने वाला है। यात्री का नाम हरदयाल पुत्र घनशू राम है। वह निज़ामुद्दीन से वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई (झाँसी) तक की यात्रा करने वाला था। सुरक्षित बचाए गए यात्री और प्लेटफार्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने RPF जवान का धन्यवाद दिया।

केजरीवाल की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, अधिकारियों को धमका रहे हैं सतर्कता विभाग के अफसर

दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने को दावा किया कि सतर्कता अधिकारी अन्य विभागों में अपने समक्ष अधिकारियों को अवैध आदेश जारी करने की धमकी दे रहे हैं। आतिशी ने अधिकारियों को फोन पर धमकी मिलने की स्थिति में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही दोनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने को दावा किया कि सतर्कता अधिकारी अन्य विभागों में अपने समक्ष अधिकारियों को अवैध आदेश जारी करने की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली की मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई उन्हें डराने व धमकाने की कोशिश करता है तो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लें।

अवैध आदेश के लिए धमका रहे अफसर

सतर्कता एवं सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी ने सोमवार को एक आदेश में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पता चला है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के अफसरों को धमकी देकर परेशान कर रहे हैं ताकि वे अवैध आदेश जारी कर सकें।

कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकारियों को आदेश

इसी को देखते हुए आतिशी ने अधिकारियों को फोन पर धमकी मिलने की स्थिति में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की मंत्री की ओर से कहा गया कि यदि अधिकारियों को सतर्कता विभाग में बुलाया जाता है और धमकियां व्यक्तिगत रूप से दी जाती हैं, तो जिस अधिकारी को धमकी दी जा रही है या डराया जा रहा है, उसे अपने फोन रिकॉर्डर पर बातचीत रिकॉर्ड करनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही दोनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि: सभी लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, 3 अक्टूबर को होगा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा जल्द सुनवाई करने की मांग मान ली है। जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। आज हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन मामले पर जल्द सुनवाई की मांग जस्टिस संजय किशन कॉल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया। वकील विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि 21 जुलाई को अंतिम बार सुना गया था। जस्टिस कौल ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है? इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौन ने कहा कि हमने इस मामले में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करता रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि 3 अक्टूबर को इस मामले को देखेंगे। हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था। ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है। न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी थी।

पासपोर्ट ऑफिस में चल रहा दलाली का खेल, पुलिस रिपोर्ट क्लीयर करने से लेकर हर चीज का है अलग रेट

गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में दलाली का खेल चल रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से पासपोर्ट बनवाने के नाम पर दलाल मोटी वसूली कर रहे हैं। बताया गया है कि वसूली का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों तक जाता है। परेशान लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए कार्यालय में ऊपर-नीचे चक्कर लगा रहे होते हैं। यही से दलाली का खेल शुरू होता है।

गाजियाबाद। आरपीओ साहब! पासपोर्ट कार्यालय में दलाली का खेल चल रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से पासपोर्ट बनवाने के नाम पर दलाल मोटी वसूली कर रहे हैं। बताया गया है कि वसूली का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों तक जाता है।

अधिकारी जान-बूझकर लगाते हैं आपत्ति

यही कारण है कि आमजन को जान-बूझकर परेशान किया जा रहा है, ताकि वह दलाल के माध्यम से काम कराने के लिए विवश हो जाएं। गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय में अधिकारी, कर्मचारी आवेदकों की मामूली कमियों पर जान-बूझकर आपत्ति लगाते हैं।

यही से दलाली का खेल शुरू होता है। परेशान लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए कार्यालय में ऊपर-नीचे चक्कर लगा रहे होते हैं। तभी पासपोर्ट कार्यालय में व आसपास घूमकर रहे दलाल उनसे संपर्क कर काम कराने के नाम पर मोटी वसूली करते हैं। जिस फाइल पर अधिकारी व कर्मचारी आपत्ति लगा चुके होते हैं, दलाल के माध्यम से सेटिंग होने पर उस फाइल की आपत्ति स्वयं दूर हो जाती हैं।

तत्काल पासपोर्ट के नाम पर ऐंठी जा रही है मोटी रकम

सर्वाधिक वसूली उनसे हो रही है जिन्हें जरूरी कारण से विदेश जाने के लिए तत्काल पासपोर्ट की जरूरत होती है। उन्हें तुंरत पासपोर्ट दिलाने के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से दलाल 30-35 हजार रुपये वसूल रहे हैं। इसके अलावा अन्य आपत्तियों को दूर कराकर पासपोर्ट बनवाने के लिए लाखों में उगाही होती है।

ऐसा नहीं है कि दलाल की सक्रियता सिर्फ गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय तक सीमित हैं। इनका नेटवर्क गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों में फैला है। इनमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व शामली 13 जिले आते हैं। इन जिलों में सक्रिय दलाल भी पासपोर्ट बनवाने के लिए मोटी उगाही कर रहे हैं।

अप्वाइंटमेंट से लेकर हर चीज का अलग है रेट

अप्वाइंटमेंट दिलाने से लेकर अटकी फाइल पास कराने के नाम पर हर काम का अलग-अलग रेट तय है। आवेदकों की पुलिस रिपोर्ट क्लीयर न आने, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम एक न होने, पता सही न भरने, अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षित की श्रेणी में आवेदन करने, कोर्ट केस छिपाने, पुराने आवेदन की जानकारी न देने, वर्तमान पता छिपाने व बायोमीट्रिक के दौरान असली दस्तावेज न दिखाने से पासपोर्ट आवेदकों की फाइल पेंडिंग में डाल दी जाती है। ऐसे आवेदकों को फाइल का निस्तारण कराने के लिए पूछताछ की अप्वाइंटमेंट लेकर गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय आना होता है।

प्रत्येक कार्य दिवस की 200 अप्वाइंटमेंट पूछताछ श्रेणी के लिए जारी की जाती है। वर्तमान में यह अप्वाइंटमेंट एक माह बाद की मिल रही है और करीब 25 हजार से ज्यादा फाइलें उपरोक्त कारणों से पासपोर्ट कार्यालय में लंबित है। बिना अप्वाइंटमेंट में कार्यालय में स्टाफ बात नहीं करता। ऐसे में फिर आवेदक दलाल के माध्यम से जाते हैं। दलाल दो-ढाई हजार रुपये में बिना अप्वाइंटमेंट के काम कराकर फाइल आगे बढ़वा देते हैं। अगर कोई बड़ी आपत्ति है तो उसका पैसा अलग से लिया जाता है।

मुझसे करें शिकायत: अधिकारी

गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, प्रेम सिंह ने कहा- पासपोर्ट की व्यवस्था ऑनलाइन है। अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझसे शिकायत करे। सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। निजी सहायक को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई आवेदक बिना अप्वाइंटमेंट के भी दूरदराज से आता है तो समस्या सुनकर निस्तारण कराएं।

महिला ने सहकर्मी पर लगाया गलत तरीके से छूने और उत्पीड़न का आरोप, मैनेजर पर केस दर्ज

दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली एक युवती से आईटी क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करने के दौरान उत्पीड़न का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर सेक्टर-40 थाने में कंपनी के मैनेजर और अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बदरपुर निवासी युवती ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सेक्टर-30 स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में आठ मई को ज्वॉइन किया था।

गुरुग्राम। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली एक युवती से आईटी क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करने के दौरान उत्पीड़न का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर सेक्टर-40 थाने में कंपनी के मैनेजर और अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

बदरपुर निवासी युवती ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सेक्टर-30 स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में आठ मई को ज्वॉइन किया था। आरोप है कि काम के दौरान कंपनी के मैनेजर ने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया। महिला कर्मचारी ने मैनेजर पर गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया।

इसके बाद गलत तरीके से उन्हें 30 अगस्त को कंपनी से निकाल दिया गया। जब उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से मैनेजर की शिकायत की तो उन्होंने भी मैनेजर का पक्ष लिया। महिला ने थाने में इसकी शिकायत दी। वहीं, लीगल एडवाइजर ने महिला की काउंसलिंग भी की। थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

CM योगी बोले- तकनीकी संस्थान घिसे-पिटे कार्यक्रमों को छोड़कर नए पाठ्यक्रम अपनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को तकनीकी संस्थानों को नए दौर के पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत.....

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को तकनीकी संस्थानों को नए दौर के पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ''तकनीकी संस्थानों को घिसे पिटे कार्यक्रम छोड़कर नए दौर के पाठ्यक्रमों को अपने यहां लागू करना होगा।''

'2017 तक UP में केवल 2 साइबर थाने थे और अब....'

सीएम योगी ने कहा कि ''आज का समय तकनीक का है, जिसका उपयोग राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण में किया जा सकता है।'' उन्होंने कहा कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे, लेकिन आज प्रदेश के हर जनपद में एक-एक साइबर थाना है। हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क है, जिसकी वजह से साइबर अपराधों पर लगाम लग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा ''विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह तकनीकी सहयोग के लिए साइबर थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करें। आज गोरखपुर जोन की पुलिस ने इस दिशा में अभिनव पहल करते हुए मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है।''

'देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है तथा राज्य के तकनीकी संस्थानों को चाहिए कि वे स्वयं को उससे जोड़ें। उन्होंने कहा ''समाज की आवश्यकता के अनुरूप हम अपने शोध को आगे बढ़ाएं। इससे परिणाम सुखद होंगे।'' उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को सुझाव दिया कि हमें समाज और सरकार की योजनाओं के सापेक्ष आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कुलपति जय प्रकाश पाण्डेय, विधायक फतेह बहादुर सिंह और विपिन सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।

भारत की पहचान है सनातन, सनातन की छाया में ही अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं

सनातन धर्म अक्षयवट है जिसकी छाया में मनुष्यता सुरक्षित है। उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उसका विस्तार आकाश में भी उतना ही अपार है। उसके आदर्श काल्पनिक नहीं यथार्थपरक हैं। वह जड़ अथवा स्थिर नहीं है, गतिमान है और परिवर्तनशील है।

डॉ. कृष्णगोपाल मिश्र

सनातन धर्म के विरुद्ध विपक्षी नेताओं के बयानों की गाली गलौज भरी बौछारें देखकर पुरानी हिन्दी फिल्म का चर्चित गीत 'अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है' याद आता है। दुनिया की यह आदत रही होगी किन्तु भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में उसकी मूलभूत विशेषता सहिष्णुता के कारण यह आदत कभी नहीं रही। गुलामी के काले दिनों में अंग्रेजों ने भारतवर्ष के धर्म, संस्कृति, शिक्षा आदि समस्त अस्मिता सूचक महान संदर्भों के विरुद्ध षड्यन्त्रपूर्वक विष उगलना प्रारम्भ किया। उनके इसी विष को यहाँ के कम्यूनिस्टों ने शिक्षा, साहित्य और कला के धरातल पर स्वतंत्र भारत में निरन्तर फैलाया और आज यही जहर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए विपक्ष के कुछ नेता उगल रहे हैं। सनातन धर्म, समानता के खिलाफ है, वह कुष्ठ रोग की तरह है, उसे डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह मिटाना होगा- आदि अपमान सूचक वाक्य देश की फिजा में गूँजकर देश-विदेश में बसे एक अरब से अधिक सनातनी हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उनकी सहिष्णुता का खुला मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें समर्थन देने वाले इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि स्वयं को चर्चा में लाने और मीडिया में छाने के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी अभिव्यक्ति की आजादी है तो इस पर कठोर प्रतिबंध लगाये जाने पर विचार करना आज की बड़ी आवश्यकता बन गयी है क्योंकि ऐसे बयानों से विपक्ष को सत्ता मिले या न मिले किन्तु सामाजिक समन्वय, सद्भाव और सहयोग अवश्य क्षत-विक्षत होगा। समाज में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए ऐसे नफरत भरे बयानों पर नियंत्रण अनिवार्य है।

सनातन धर्म भारतवर्ष का अपना धर्म है। उसके सिद्धान्त शाश्वत हैं और न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समस्त विश्व के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। हजारों वर्ष पूर्व सनातन धर्म ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का उदार भाव व्यक्त किया और आज भी वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों की समापन वेला में 'विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो'- जैसे उद्घोष गुंजित कर अपनी मूल्य चेतना को स्वर देता है। प्रकृति के साथ उसकी गहरी रागात्मकता है जो नदी, सागर, पर्वत, वन, बादल, भूमि, वायु आदि में देवत्व का दर्शन कराती है और प्राकृतिक पर्यावरण की शुद्धता के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है। सनातन धर्म के अद्वैत दर्शन ने मनुष्य के साथ-साथ जीवमात्र में परम सत्ता का दर्शन देकर पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों तक की रक्षा का प्रावधान किया है। सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ श्रीमद्भगवदगीता ब्राह्मण, गाय हाथी, कुत्ता, चाण्डाल सब में एक ही ईश्वर की उपस्थिति निर्देशित कर जीवमात्र की समानता का शंखनाद करता है। वैदिक युग से लेकर आज तक उसका प्रवाह निर्बाध रहा है। शास्त्र और शस्त्र सनातन धर्म की दो सशक्त भुजाएं हैं। राम, कृष्ण और शिव उसके प्रतीक आदर्श हैं। भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले छोटे-बड़े करोड़ों मंदिर, चैरे, चबूतरे उसके ऊर्जा केन्द्र हैं और असंख्य साधु-संन्यासी उसके संरक्षक हैं। उसे मिटाने की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है।

सनातनी धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने में अग्रणी हैं। शकों और हूणों जैसे बर्बर आक्रान्ताओं पर विजय प्राप्त करने वाला सनातन धर्म गजनवी, गोरी, तैमूर, औरंगजेब, नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली जैसे आक्रान्ताओं से टकराकर भी नहीं टूटा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए पादरियों के कुचक्र और प्रलोभन उसे लुभा न सके। हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद भी उसकी विजय-पताका सबसे ऊँची है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान की सर्वस्वीकृति उसकी साक्षी है।

सनातन दूर्वा है। उसमें दूर्वा की तरह झुककर पैरों तले रौंदे जाने पर भी अपने अस्तित्व को बचा ले जाने की अद्भुत क्षमता है। विधर्मी आक्रमणों और कुटिल षड्यंत्रों की कड़ी धूप में सूख जाने पर भी वह अवसर पाकर हरी हो उठती है।

सनातन अमरवेल है। उसे अपने विस्तार के लिए कभी राजसिंहासन का सहारा नहीं लेना पड़ा। वह राजपुत्रों और राजवंशों से पोषण पाकर नहीं फैली। उसे अपने प्रसार के लिए आक्रमणकारी सैनिकों और सेवा का आडम्बर रचते प्रलोभनकारी व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड़ा। सनातन धर्म की अमरवेल अपने उदार चिन्तन और मानवीय मूल्यों के कारण बिना आश्रय के ही फल-फूल रही है। विश्व में प्रतिष्ठित हो रहे नए मंदिर इसके प्रमाण हैं। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में मंदिर निर्माण सनातन की नयी प्रतिष्ठा है। इस्कान द्वारा स्थापित कृष्ण मंदिरों की बढ़ती संख्या सनातन धर्म की अमर बेल का नूतन विकास है।

सनातन धर्म अक्षयवट है जिसकी छाया में मनुष्यता सुरक्षित है। उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उसका विस्तार आकाश में भी उतना ही अपार है। उसके आदर्श काल्पनिक नहीं यथार्थपरक हैं। वह जड़ अथवा स्थिर नहीं है, गतिमान है और परिवर्तनशील है। उसमें अपने अंदर समय के साथ आने वाली विकृतियों को स्वयं दूर करने की अद्भुत क्षमता है। गति, परिवर्तन, परिष्करण, संशोधन उसके मूलतत्व हैं। इसलिए वह चिर पुरातन और नित नवीन है। उसकी पृष्ठभूमि में विराट इतिहास है और उसके समक्ष अनन्त भविष्य। सनातन मनुष्य की रचनात्मक प्रज्ञा का अक्षय प्रवाह है। नकारात्मक नारों का भ्रामक प्रचार उसे रोक नहीं सकता।

विगत शताब्दियों में परतंत्रता जनित प्रभावों के कारण सनातन में आयी छुआछूत, पर्दा, बालविवाह, आदि विकृतियों पर विजय पाने की ओर सनातन का विजय-रथ निरन्तर अग्रसर है। सनातन को कोसकर समाज में जहर घोलने वाले इन तथाकथित बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों और नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब से लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत भ्रमण पर आने वाले विदेशी चीनी यात्री हवेनसांग ने भारतीय समाज की जिस सुख, शान्ति, समृद्धि का उल्लेख किया है वह सनातन चिन्तन परम्परा की ही देन है। भारत सोने की चिड़ियां सनातन व्यवस्था की छाया में ही रहा। अयोध्या नरेश सत्यवादी हरिश्चन्द्र को काशी के डोम ने खरीदा था इस संदर्भ से भी प्राचीन भारत में सनातन व्यवस्था में दलित समझे जाने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति का अनुमान करना चाहिए। लगभग सौ वर्ष पूर्व सवर्ण वर्ग में जन्मे महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना कर सनातन धर्म में संशोधन करते हुए अस्पृश्यता के अभिशाप को दूर करने की दिशा में देशव्यापी सार्थक प्रयत्न किये। कथित ऊंची जातियों में जन्म लेने वाले वीर सावरकर, महात्मा गाँधी, डॉ. हेडगेवार, प. श्रीराम शर्मा आचार्य आदि ने सनातन में आए सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए गंभीर प्रयत्न किये जिनका शुभ परिणाम स्वतंत्र भारत में धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक धरातल पर आज सबके सामने हैं। मंदिरों के द्वार सबके लिए खुले हैं। आज चाय की गुमठियों, होटलों और चाट के ठेलों पर खाने-पीने का सामान बनाने वालों की जाति नहीं पूछी जाती। सामाजिक समरसता के इन प्रयत्नजनित सकारात्मक परिवर्तनों ने सनातन को नई शक्ति दी है। जिन गाँवों-कस्बों में अभी भी हठपूर्वक छुआ-छूत जैसे अपराध यदि कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाहियाँ हो रही हैं। जितना घना अंधेरा कल तक था उतना आज नहीं है। जो आज बचा है वहै कल नहीं रहेगा। इस आशा और विश्वास के साथ सनातन समाज आगे बढ़ रहा है। उसने तुलसीदास के उस रामराज्य की स्थापना को चुना है जिसमें चारों वर्णों के लोग राजघाट पर साथ-साथ स्नान करते हैं-

राजघाट सब विधि सुंदर वर।
मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर।।

किंतु सामाजिक समरसता के इस राजघाट का निर्माण दलित और सवर्ण की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। वह उनकी आँख की किरकिरी बन रहा है क्योंकि इसके कारण उन्हें सत्ता स्वयं से छिटकती दिख रही है। उनकी बौखलाहट बढ़ रही है और वे वाणी का विवेक और संयम खोकर स्वयं को ही कोस रहे हैं। सनातन को कोसने वालों का मूल भी सनातन में ही है क्योंकि सनातन ही भारत की पहचान है। संसार के अन्य देश भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत यहाँ के मठों, मंदिरों, धर्म ग्रंथों, पर्व-उत्सवों, राम-कृष्ण आदि महापुरुषों से ही जानते हैं।

सनातन है तो भारत है। सनातन नहीं तो भारत नहीं, भारत की पहचान नहीं। सनातन की छाया में ही भारत में अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं। विगत सात दशकों का इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान और बंगलादेश में सनातन के अल्पमत में आते ही वहाँ अन्य धर्मों के अनुयायी सुरक्षित नहीं रहे। अफगानिस्तान में सनातन पूरी तरह निर्मूल हुआ है तो वहाँ बौद्ध, जैन और सिख आदि भी नहीं बचे हैं। जिस धर्म-निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की दुहाई हमारे विपक्षी नेता देते हैं उसकी सुरक्षा सनातन की पुष्टि में ही है, उसके निर्मूलन में नहीं।

विभागाध्यक्ष-हिन्दी
शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नर्मदापुरम्म.प्र.

बजाज ऑटो ने भारत की पसंदीदा 150सीसी पल्सर N150 को एक नए अवतार में लॉन्च किया

- बेहतर ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के लिए 13.5 एनएम टॉर्क और सिंगल-चैनल एबीएस के साथ 14.5 पीएस पीक पावर की सुविधा है।
- मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और एक स्पोर्टी अंडरबेली एग्जॉस्ट
- यह बाइक तीन आकर्षक रंगों - रेसिंग रेड, एबोनी ब्लैक और मेटालिक पर्ल व्हाइट में उपलब्ध होगी
- कीमत 1,18,029 एक्स-शोरूम

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया और तिपहिया कंपनी बजाज ऑटो ने भारत में बिल्कुल नई पल्सर N150 लॉन्च की। पल्सर एन150 विस्तारित पल्सर पोर्टफोलियो के लिए एकदम सही जोड़ है, जिसने पिछले 18 महीनों में कई सनसनीखेज लॉन्च देखे हैं, जिनमें अब तक का सबसे बड़ा पल्सर एन250 और अविश्वसनीय रूप से सफल पल्सर एन160 शामिल हैं। पल्सर एन150 के साथ, भारत की सबसे अधिक बिकने वाली स्पोर्ट्स बाइक परिवार को एक योग्य नया सदस्य मिला है जो न केवल पल्सरमेनियाक्स की विरासत को बनाए रखने का वादा करता है बल्कि कई नए लोगों को भी इसमें शामिल करेगा।

डिज़ाइन भाषा गतिशील और ऊर्जावान चरित्र रेखाओं, सख्त अनुपात और आधुनिक एयरो गतिशीलता का दावा करती है। मस्कुलर टैंक की तुलना एक चिकने, स्टाइलिश कमर अनुभाग से की जाती है जो एक समोच्च स्टेप सीट तक फैला हुआ है, जो एक आकर्षक प्रोफ़ाइल बनाता है। यह एक स्पोर्टियर अंडरबेली एग्जॉस्ट से लैस है जो उच्च आरपीएम पर गुर्राता है। बेली पैन, फ्रंट फेयरिंग और फ्रंट फेंडर जैसे फ्लोटिंग बॉडी पैनल प्रभावशाली प्रोफ़ाइल को पूरा करते हैं।

बजाज ऑटो के अध्यक्ष (मोटरसाइकिल) सारंग कनाडे ने कहा, ₹बीस साल पहले, हमने पहली पल्सर 150 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, जिसने एंट्री-लेवल स्पोर्ट बाइकिंग सेगमेंट को हिलाकर रख दिया था और तब से यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 150 सीसी मोटरसाइकिल रही है। N150 के साथ, पल्सर अपने सबसे बड़े और बोल्ड अवतार में सड़क पर राज करने के लिए वापस आ गया है। इसकी आक्रामक स्टाइलिंग, सेगमेंट-अग्रणी विशेषताएं, शानदार ऑन-रोड प्रदर्शन और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक कीमत इसे पल्सर परिवार के लिए एक शानदार मूल्यवर्धन बनाती है। हमारा लक्ष्य हर किसी के लिए सवारी के आनंद को सुलभ बनाना है और यह नई बाइक उस मिशन का प्रमाण है।

प्रदर्शन: नई बजाज पल्सर एन150 दो पहियों पर एक पावरहाउस है, जो प्रभावशाली 14.5 पीएस पीक पावर और 13.5 एनएम टॉर्क का दावा करती है। इसका चौड़ा टॉर्क बैंड वास्तव में इसे अलग करता है, जो निचले सिरे से लेकर शीर्ष तक, संपूर्ण आरपीएम रेंज में बहुत अधिक उपयोगी टॉर्क प्रदान करता है। इस मोटरसाइकिल के साथ, सवार किसी भी सवारी स्थिति में रोमांचकारी प्रदर्शन और सहज गतिशीलता का अनुभव कर सकते हैं। जब सवार सुरक्षा की बात आती है, तो पल्सर N150 भारी जीत हासिल करता है। सिंगल-चैनल एबीएस बेहतर ब्रेकिंग नियंत्रण और ट्रैक्शन प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सवार किसी भी मुश्किल सड़क पर आसानी से चल सकें। शक्ति, सटीकता और सुरक्षा का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण, पल्सर एन150 सवारी के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है।

बजाज ऑटो के अध्यक्ष (मोटरसाइकिल) सारंग कनाडे ने कहा, ₹बीस साल पहले, हमने पहली पल्सर 150 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी, जिसने एंट्री-लेवल स्पोर्ट बाइकिंग सेगमेंट को हिलाकर रख दिया था और तब से यह भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 150 सीसी मोटरसाइकिल रही है।

नई Tata Nexon EV खरीदें या MG ZS EV ?, खरीदने से पहले जानें हर जरूरी बात

टाटा मोटर्स ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है. माना जा रहा है कि यह मॉडल मार्केट में पहले से मौजूद एमजी जेडएस ईवी मॉडल के लिए जबरदस्त टक्कर देगा.

चार पहिया वाहन क्षेत्र में कंपनियां काफी तेजी से अपने इलेक्ट्रिक मॉडल को लॉन्च कर रहे हैं इसी कड़ी में हाल में ही दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. इस आर्टिकल में हम 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट (2023 Tata Nexon EV) और एमजी मोटर की जेडएस ईवी मॉडल (MG ZS EV) की आपस में तुलना करेंगे.

2023 Tata Nexon EV facelift मॉडल का बैटरी पैक

मोटर्स कंपनी ने 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं पहले वेरिएंट मिड रेंज और दूसरा लॉन्ग रेंज है. इन दोनों वेरिएंट में अलग तरह का बैटरी पैक भी दिया गया है. मिड रेंज में करीब kWh बैटरी पैक दिया गया है जबकि लॉन्ग रेंज में 40.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है.

MG ZS EV मॉडल का बैटरी पैक

एमजी जेडएस ईवी मॉडल के मार्केट में पांच वेरिएंट उपलब्ध है हम केवल एमजी जेडएस ईवी मॉडल कि बात करें तो कंपनी की तरफ से इसमें 50.3 kWh बैटरी पैक की सुविधा दी गई है. रेंज की बात करें तो बैटरी को एक बार चार्ज कर लेने पर यह करीब 461 किलोमीटर की रेंज को टच कर सकता है.

2023 Tata Nexon EV facelift मॉडल का पावर

पावर की बात करें तो 2023 टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट मॉडल में जेन2 मोटर दिया गया है मिड रेंज वेरिएंट की बात करें तो यह करीब 127 बीएचपी अधिकतम पावर और 215 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट कर सकता है वही लॉन्ग रेंज वेरिएंट की बात करें तो यह करीब 143 बीएचपी अधिकतम पावर और 215 एनएम टॉर्क जनरेट कर सकता है.

MG ZS EV मॉडल का पावर

एमजी जेडएस ईवी मॉडल के पावर कैपेसिटी की बात करें तो यह मोटर चालू करने पर 174.33 बीएचपी की पावर और 280 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है.

आ गया 200 KM की रेंज वाला ई स्कूटर, 3 सेकेंड में पकड़ेगा 40 की रफ्तार, 65 Kmph की टॉप स्पीड

इलेक्ट्रिक वन ने अपने दो नए ई स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं.
इलेक्ट्रिक वन ने अपने दो नए ई स्कूटर इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं.

नई दिल्ली. देश में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ती जा रही है. चलाने में किफायती व लंबे समय तक चलाए जा सकने वाले इन व्हीकल्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. कारों के साथ ही बाइक्स और स्कूटर के इलेक्ट्रिक अवतार भी अब देश में लगातार लॉन्च हो रहे हैं. इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक वन ने अपना ई 1 एस्ट्रो प्रो सीरीज को लॉन्च किया है. गौरतलब है कि देश में 80 शहरों में कंपनी के 100 से ज्यादा स्टोर्स और सर्विस स्टेशंस हैं. स्कूटर में कंपनी ने शानदार फीचर्स दिए हैं. इसी के साथ इसकी रेंज भी काफी शानदार दी गई है.

जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपनी प्रो सीरीज में ई1 ऐस्ट्रो प्रो और ई 1 ऐस्ट्रो प्रो 10 इंडिया में लॉन्च किया है. स्कूटर की कीमत 99,999 रुपये और 1,24,999 रुपये ऑन रोड है. खास बात ये है कि इन दोनों ही स्कूटर्स का पिक अप है. स्कूटर को कंपनी 5 कलर ऑप्शंस में ऑफर कर रही है. इसमें आपको रैड बैरी, ब्लेज ऑरेंज, ऐलीगेंट वाइट, मैटेलिक ग्रे और रेसिंग ग्रीन कलर देखने को मिलेगा.

मिलेगी शानदार रेंज

जानकारी के अनुसार स्कूटर में कंपनी ने 72 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी लगाई है. ये बैटरी 2000 वॉट की मोटर से कनेक्टेड है. स्कूटर की रेंज सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर की है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है. स्कूटर केवल 2.99 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है. वहीं इसको फुल चार्ज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है.

इन राज्यों में मिलेगा

फिलहाल कंपनी का स्कूटर आपको गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व असम में उपलब्ध होगा. आने वाले समय में कंपनी 20 और शहरों में अपना विस्तार करने जा रही है. भारत के साथ ही कंपनी श्रीलंका और नेपाल में भी अपने शोरूम खोलने जा रही है. फिलहाल कंपनी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, तुर्कि और इंडोनेशिया में अपने स्कूटर बेचती है. इलेक्ट्रिक वन ऐनर्जी के संस्थापक व सीईओ अमित दास ने कहा कि कंपनी ने मानेसर गुरुग्राम में इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग सैटअप तथा दुनिया के अग्रणी सप्लायरों के साथ गठबंधन किया है. ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और हम ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

भारत की अध्यक्षता व जी-20 के परिणाम

डा. अश्विनी महाजन

जी-20 सम्मेलन के दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु और सतत वित्त पर काम करने का आह्वान किया गया है, ताकि इसके माध्यम से सबसे बड़ी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके'

जी-20 शिखर सम्मेलन 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आयोजन भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत के लिए अपनी विविध प्रकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन करके दुनिया को प्रभावित करने का एक अवसर था। भारत के कौशल की भी परीक्षा चल रही थी कि क्या हम वैश्विक नेताओं को रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचा सकते हैं, और विकासशील देशों, जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, के सामने आ रही आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। राजनयिक हलकों में इसे आश्चर्य के रूप में लिया गया कि जी-20 के पिछले बयान की तुलना में, जिसमें रूस की 'आक्रामकता' के लिए उसकी 'निंदा' की गई थी, दिल्ली घोषणापत्र में 'विश्वास की कमी' की बात की गई है और वर्तमान में चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर इस विश्वास की कमी को हल करने की आवश्यकता है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश यह नहीं मान सकते कि जी-20 का रुख नरम हो गया है, लेकिन हम 'लिखित' में यही देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन और उसके निष्कर्षों को लेकर न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी काफी उत्सुकता थी। भारत की ओर से इसके लिए न केवल भौतिक तैयारी, बल्कि बौद्धिक तैयारी भी पूरी गंभीरता से की गई थी। अब जब यह सम्मेलन संपन्न हो गया है तो यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि इस सम्मेलन के निष्कर्ष दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं? यह समझना होगा कि यह सम्मेलन कई मायनों में बहुत महत्व रखता है।

जी-20 दिल्ली शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम, समूह में अफ्रीकी संघ का प्रवेश रहा। अफ्रीकी संघ के शामिल होने से पहले, जी-20 दुनिया की दो-तिहाई आबादी, दुनिया की 85 प्रतिशत जीडीपी और 75 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन जी-20 में अफ्रीकी संघ के प्रवेश के बाद, अब यह दुनिया की 82 प्रतिशत आबादी, दुनिया की 88 प्रतिशत जीडीपी और लगभग 84 प्रतिशत वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इस बदलाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब ग्लोबल साउथ न केवल बहुसंख्यक आबादी का ही प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक व्यापार में भी उसका बड़ा हिस्सा है। यह उम्मीद करना उचित है कि यह बदलाव अब जी-20 के कामकाज और निर्णयों में दिखाई देने लगेगा। वैश्विक तनाव और उथल-

पुथल के बावजूद, न केवल घोषणा पर आम सहमति बन सकी, बल्कि जो निष्कर्ष निकले, वे इस सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए ध्येय वाक्य 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के अनुरूप प्रतीत होते हैं। इस जी-20 शिखर सम्मेलन की खासियत यह रही कि भारत ने शुरुआत से ही 'ग्लोबल साउथ' के हितों की रक्षा की बात की। इसके मुताबिक, सम्मेलन के अंत में निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत अपनी बात पर खरा उतरा।' यानी भारत ने जो कहा, वो किया। जी-20 सम्मेलन की खासियत यह रही कि इसमें विकासशील देशों की आकांक्षाओं पर न सिर्फ बात की गई, बल्कि उस दिशा में कदम भी उठाए गए।

अब यह देखने का समय है कि दिल्ली घोषणापत्र किसी भी तरह से विकसित देशों की ओर झुका हुआ नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि इस बार इसका फोकस वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ पर अधिक था। सम्मेलन की पहली उपलब्धि यह रही कि सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को बेहतर, बड़ा और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि वे दुनिया के देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। भारत हमेशा से वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधारों का पक्षधर रहा है। इस संदर्भ में, इस बात पर सहमति हुई कि बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) की पूंजी संरचना में बदलाव होना चाहिए। इस शिखर सम्मेलन में, एक स्वतंत्र पैनल की सिफारिशों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता ढांचे (सीएएफ) के माध्यम से इन एमडीबी में सुधार सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इस शिखर सम्मेलन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 'क्रिप्टो' को विनियमित करने को लेकर है। भारत ने कराधान के माध्यम से क्रिप्टो को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अपने स्वतंत्र प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले भी इस संबंध में दुनिया से समन्वय और आपसी सहयोग का आह्वान किया था। जी-20 शिखर सम्मेलन इस संबंध में वैश्विक सहमति बनाने का एक उपयुक्त अवसर था। दिल्ली घोषणा में कहा गया है कि जी-20 देश क्रिप्टो परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के जोखिमों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। घोषणा में कहा गया, 'हम क्रिप्टो-परिसंपत्ति गतिविधियों और बाजारों और वैश्विक स्थिर कॉइन व्यवस्था के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की उच्च स्तरीय सिफारिशों का समर्थन करते हैं।' इसके अलावा घोषणा में विशेष रूप से, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी), डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, डिजिटल इको-सिस्टम को बढ़ावा देने पर अलग-अलग उप-खंड हैं। इन मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत पहले से ही इन मुद्दों पर अपने समकक्ष देशों से बहुत आगे है। लंबे समय से विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों, खासकर तकनीकी कंपनियों, सोशल मीडिया कंपनियों और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कर परिहार (टैक्स अवॉयडेंस) की समस्या से जूझ रहे हैं। इन कंपनियों के बहुराष्ट्रीय होने के कारण कर प्रणाली पर वैश्विक सहमति के अभाव में इन कंपनियों को उचित तरीके से कर के दायरे में लाना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में आम सहमति के संदर्भ में जी-20 दिल्ली घोषणापत्र में व्यापक चर्चा की गई है। यह कहा जा सकता है कि यह 'कार्य प्रगति पर' है। भविष्य में इस पर वैश्विक सहमति बनने पर इन कंपनियों से टैक्स वसूलना आसान हो जाएगा। इससे विकसित और विकासशील दोनों देशों की जनता को फायदा होगा। यह इस सम्मेलन की तीसरी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।

आज कई विकासशील देश कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, जिसके कारण उनकी अर्थव्यवस्थाएं संकट में हैं। जी-20 दिल्ली घोषणापत्र में वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन का आह्वान किया गया है। घोषणापत्र में जाम्बिया, घाना, इथियोपिया और श्रीलंका की ऋण स्थिति को हल करने की भी बात कही गई है। यह इस शिखर सम्मेलन की चौथी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस शिखर सम्मेलन की एक और बड़ी उपलब्धि जलवायु वित्त को लेकर है। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने एक बड़ा संकट बनकर उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती की भयावहता की तुलना में इससे निपटने के प्रयास बेहद अनिर्णायक और आधे-अधूरे प्रतीत होते हैं। कोई भी वैश्विक मंच हो, विकासशील देशों की हमेशा यही शिकायत रही है कि अतीत में विकसित देशों द्वारा किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। पहले विकसित देशों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उनकी ओर से 100 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन अब तक, वे वायदे के अनुसार सहायता प्रदान करने में विफल रहे हैं। इतना ही नहीं, वे इस संकट से निपटने के लिए तकनीक हस्तांतरित करने को भी तैयार नहीं हैं। मानवता विकसित देशों द्वारा यह सहायता देने के लिए अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इस जी-20 सम्मेलन के दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु और सतत वित्त पर काम करने का आह्वान किया गया है, ताकि इसके माध्यम से मानवता के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

संपादक की कलम से

रोजगार के सवाल

भारत में बेरोजगारी और महंगाई सबसे अहम राष्ट्रीय मुद्दे हैं। विडंबना है कि इन मुद्दों पर अधिकतर जनादेश तय नहीं किए जाते। आजकल महिला आरक्षण की खूब गहमागहमी है। सामान्य आरक्षण भी ऐसा ही संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण से ज्यादा जरूरी रोजगार है, ताकि महिलाएं भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी 'अवैतनिक कामकाजी' न रह सकें और औसत भारतीय आत्मनिर्भर बन सके। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी आजकल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करें या 'यशोभूमि' इवेंट कॉन्प्लेक्स का उद्घाटन करें अथवा किसी प्रदर्शनी में जाएं, तो वह हर जगह रोजगार की बढ़ोतरी के दावे करते हैं। देश में बड़े-बड़े राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे भी बनाए जा रहे हैं, जाहिर है कि उनमें भी रोजगार पैदा होते होंगे। उनके निर्माण के समानांतर अन्य आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। बेशक हमारी अर्थव्यवस्था की विकास-दर करीब 8 फीसदी है, लेकिन प्रति व्यक्ति इसका औसत करीब 4.5 फीसदी ही है। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद भारत की आर्थिकी ने बहुत तेज और सकारात्मक वापसी की है, लिहाजा 2021-22 में न केवल जीडीपी करीब 150 लाख करोड़ रुपए थी और बीते साल की अपेक्षा 9 फीसदी ज्यादा भी रही, बल्कि वह कोरोना-पूर्व के स्तर को भी लांघ गई। जीडीपी का अर्थशास्त्र कुछ भिन्न होता है, जिसे आम आदमी समझ नहीं पाता, लिहाजा आर्थिक विकास और सामान्य रोजगार की दर में गहरे विरोधाभास दिखाई देते हैं। कई अनुत्तरित सवाल भी निहित होते हैं। राजनीतिक सत्ताएं उनके जवाब नहीं देतीं।

रोजगार भी ऐसा ही मुद्दा है, जो तमाम सकारात्मक आर्थिक विकास के बावजूद पूरी तरह संबोधित नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में रोजगार, नौकरी और स्वरोजगार की अलग-अलग व्याख्याएं और कहानियां हैं। भारत सरकार की विभिन्न रपटों के डाटा से स्पष्ट है कि नौकरी के बाजार में लचीलापन या रोजगार की वापसी हुई है। सरकारों के अलावा, निजी क्षेत्र में भी बंपर रोजगार के अवसर विज्ञापित किए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं और युवा स्नातकों के लिए ये अवसर समूची अर्थव्यवस्था से पिछड़ गए हैं। कोरोना महामारी के बाद पुरुष और महिला कामगारों की दर बढ़ी है, लेकिन रोजगार का यह डाटा सतही तौर पर ही सुर्खियों में रहा है। यदि कामकाज के हालात सुधरे हैं, तो जाहिरा तौर पर बेरोजगारी की दर कम होनी चाहिए, लेकिन आज भी यह राष्ट्रीय दर 7-8 फीसदी के बीच झूल रही है। 2021-22 में बेरोजगारी दर करीब 6.6 फीसदी थी, जो 2019-20 की तुलना में करीब 2 फीसदी कम थी, लेकिन महिला रोजगार में बढ़ोतरी दिखाई जा रही थी। यह कैसी विसंगति थी? एक रपट बताती है कि महिला रोजगार में संरचनात्मक ह्रास हुआ है। इसी के विरोधाभास में बताया गया कि महिलाओं के स्वरोजगार के रुझान बढ़े हैं। यह स्वरोजगार 'अवैतनिक' था और 'मैदान छोड़ने' का एक विकल्प था, क्योंकि बाजार में नौकरियों और रोजगार के बुरे हालात थे। यह भी निष्कर्ष दिया गया कि 2019-20 और 2020-21 की तुलना में महिलाओं की मासिक आमदनी बढ़ी है। इसे भी मुद्रास्फीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दिलचस्प है कि 2021-22 में जिसकी मासिक आय 12089 रुपए थी, वह 2017-18 की औसतन मासिक आय से करीब 2 फीसदी कम थी। यह कैसे संभव है? व्यक्ति की आय साल-दर-साल बढ़ती है या घटती जाती है?

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की मासिक आमदनी को बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों की सरकारें अपनी वित्तीय नीतियां उसी के अनुरूप बनाती हैं। कोई 1500 रुपए, तो कोई 2000 रुपए और 2500 रुपए मुफ्त में बांटने की घोषणा करता है। वह नियमित आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि मुफ्त की राशि कभी मिल जाती है, तो कभी सरकारें भूल भी जाती हैं। ऐसे लॉलीपॉप के बावजूद देश के श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तनाव तो बरकरार हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। युवा बेरोजगारी तो एक चिंतित सरोकार है, जो कभी-कभार अराजकता का रूप भी धारण कर लेता है। डाटा से स्पष्ट है कि नौकरी ढूंढने वाले स्नातकों या उससे अधिक शिक्षित वर्ग में औसतन 29 साल की उम्र तक 20 फीसदी से ज्यादा बेरोजगारी है। कमोबेश प्रधानमंत्री को तो इसका एहसास होगा!

राय

हर आगंतुक, पर्यटक नहीं-1

पर्यटन की तहजीब में आ के हर साल एक हफ्ता गुजर जाता, लेकिन इस उद्योग की व्याख्या में यह कोई स$फर नहीं। पर्यटन अगर साल में अपने लिए कुछ दिन, कुछ महीने तय करने लगे तो हम इसके चबूतरे पर केवल नौटंकी करते रहेंगे। पर्यटन की आत्मा में चौबीस घंटे का अनुभव, गतिविधियां व श्रम समाहित रहता है। पर्यटक हर देश, हर प्रदेश और हर जगह के संदेश को समझता है। पर्यटक अगर अंतरराष्ट्रीय डगर पर निकला है, तो उसे भारत बुलाने का मकसद बड़ा हो जाता है। ऐसे में हिमाचल को सर्वप्रथम देश में खुद को डेस्टिनेशन बनाना है और फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का सपना पूरा करना है। बेशक इस आरजू में कुछ मात्रात्मक उपलब्धियां रही हैं और जिनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय सैलानी प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन आने के कारणों को और सकारात्मक तथा पर्यटकों की श्रेणी को हाई एंड तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। हिमाचल में पर्यटन पर व्यावहारिक अनुसंधान के साथ-साथ इसके रुझान की व्यावसायिक समीक्षा जरूरी है। यह केवल प्रचार सामग्री या तयशुदा आकर्षणों का गुलदस्ता नहीं, बल्कि पर्यटन क्षेत्र की जरूरतों को प्राथमिकता देने का इंतजाम है। भले ही आंकड़ों में हिमाचल के पर्यटन की तस्वीर खुशहाल है, लेकिन इससे हासिल आर्थिकी को अपेक्षित बल नहीं मिल रहा। इसी साल जून तक हिमाचल में पर्यटन आगमन का आंकड़ा एक करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2017 के 196 लाख के शिखर से आगे बढ़ सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल में आते हर शख्स को पर्यटक गिना जा रहा है, जबकि इस संख्या में अवांछित तत्व शरीक हैं। जाहिर तौर पर हर आगमन को पर्यटन के लिए गिनेंगे, तो इस उद्योग से वांछित आर्थिकी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए गोवा को ही लें जहां दिसंबर से जनवरी तक मात्र ढाई लाख विदेशी पर्यटक आए और साल भर में हर तरह के केवल 81 लाख सैलानी ही अपेक्षित हैं। दूसरी ओर 2022-23 में अब तक 348 चार्टर फ्लाइट्स गोवा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुकी हैं जिनके माध्यम से 1.4 लाख सैलानी पहुंचे। ये तमाम पर्यटक एक खास प्रभावशाली कैटेगिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गोवा के आकर्षण को हाई एंड टूरिस्ट का प्रिय डेस्टिनेशन बना देते हैं। ऐसा दम जून तक हिमाचल में आए पर्यटकों की संख्या में नहीं है। गोवा में आने वाले पर्यटक का बजट हिमाचल में आने वालों से कई गुना अधिक इसलिए होता है क्योंकि वे अधिक दिनों के ठहराव में उच्च स्तर की सुविधाओं पर व्यय करते हैं। हिमाचल में पर्यटक और पर्यटन की पहचान अभी निम्न स्तर पर है। मसलन अस्सी फीसदी पर्यटक धार्मिक यात्रा के पड़ाव की तरह आते हैं और इनके समागम चंद दिनों की ऐसी चांदनी है, जो आम हिमाचली के दैनिक व्यय से भी कम ठहरती है। चिंतपूर्णी या अन्य धार्मिक स्थलों की लंगर परंपरा में प्रायः धार्मिक पर्यटकों को मुफ्त भोजन उपलब्ध रहता है और ठहरने की व्यवस्था भी बिना किसी व्यय के हो जाती है। इसी के साथ ट्रक व ट्रैरक्टर पर्यटन की परंपरा में जत्थे तो खूब आते हैं, मगर एक-दो दिन के भ्रमण में यह ऐसा कारवां है, जो अपनी रसोई भी साथ लेकर चलता है। ऐसे में अस्सी फीसदी पर्यटकों का बोझ उठाकर हिमाचल केवल श्रद्धा के आंकड़ों को पर्यटन में बटोर रहा है, न कि आर्थिकी में इसकी कोई महत्त्वपूर्ण भागीदारी हो रही है। बेशक मंदिर आय या धार्मिक नगरियों के व्यवसाय में रौनक दिखाई दे, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक पर्यटन का दोहन नहीं हो रहा। इसके लिए टेंपल टूरिज्म की एक अलग नीति, प्रबंधन व मौलिक सोच होना चाहिए। मंदिरों के साथ उपहार केंद्र तथा उपहार एवं प्रसाद उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। -क्रमशः

बजरंग बली और चुनाव

देश में फैल रही नफरत, मिथ्या प्रचार और बात-बात पर नेताओं द्वारा बोले जाने वाले झूठ से परेशान होकर एक दिन मैं बजरंग बली से आर्तनाद स्वर में प्रार्थना करने लगा, 'हे प्रभु! इससे पहले धरा पर पापों का भार इतना बढ़ जाए कि शेषनाग फन पर धरती को संभाल पाने में असमर्थ रहने पर उसे सागर में गिरा दें और जल प्रलय हो उठे, आप फौरन प्रकट हों। समाज सेवा और देश सेवा के नाम पर बार-बार झूठ बोलने, धन कमाने और जनता को बेवकूफ बनाने वालों का नाश करने के बाद देश में सत्य का साम्राज्य स्थापित करें।' मेरी पुकार सुनकर हनुमान प्रकट तो हुए किन्तु किसी हारे हुए नेता की तरह खीजे स्वर में बोले, 'कर्नाटक चुनावों में छद्म हिन्दुवादियों के बार-बार आवाह्न से तंग होकर मैं झोला उठा कर हिमालय चला गया था। तुम्हारी प्रार्थना पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन धर्म के नाम पर धंधा चलाने वालों से मैं अप्रसन्न हूँ।' मैं बोला, 'हे प्रभु! आपने मेरी विनती स्वीकार की। इसके लिए आपका धन्यवाद। नहीं तो पक्के घर के लिए सरकार को कई आवेदन देने के बावजूद अभी तक इस टपरिया में पड़ा हूँ, जबकि साल 2022 कब का बीत चुका है। हर घर शौचालय के नाम पर रेल की पटरी पर लोटा लेकर जाता हूँ। पर आप वेश बदल लें। मैं तो आम लोगों की तरह दिखता हूँ। ज़माना नंगई का है। मेरे निर्वस्त्र घूमने पर भी लोग सहज महसूस करेंगे। पर आपको इस वेश में देख कर बिदक जाएंगे।' केसरी नन्दन तनिक गुस्से में बोले, 'अरे मूढ़! मुझे पूरा आर्यावर्त जानता है।

मैं क्या अमेरिका जा रहा हूँ जो मुझे वेश बदलना होगा।' मैंने कहा, 'प्रभु! लगता है आप कलियुग के प्रताप से परिचित नहीं। आज राम भी केवल तभी प्रकट हो सकते हैं, जब भाजपा चाहे। क्या आपने अयोध्या में राम मन्दिर के भूमि पूजन पर लगा वह पोस्टर नहीं देखा जिसमें डंकेश भगवान राम का हाथ पकड़ कर उन्हें मन्दिर के भीतर ले जा रहे हैं। घट-घट में बसने वाले श्रीराम को मन्दिर लोकसभा चुनावों से पहले ही नसीब होगा। क्या आपने देवों के देव परिधान मंत्री का जलवा नहीं देखा। कभी बुलेट ट्रेन की बुलेट फैंकने वाले देवों के देव ने कल लाल क़िले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता सम्बोधन में वंदे भारत ट्रेन को बुलेट ट्रेन बता दिया था। पर उनकी झूठ की गुगली तब नो बॉल हो गई जब उन्होंने बिहार के दरभंगा में तालाब में नहाती भैंसों के बीच एम्स खोल दिया।' बजरंगी सोचते हुए बोले, 'वत्स! तुम सही कहते हो। पर मैं तुम्हारे परिधानमंत्री के चरित्र की दृढ़ता का क़ायल हूँ। जो व्यक्ति मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड की घटना से नहीं हिला, वह अवश्य ही बाली से अधिक बलशाली होगा। लेकिन मैं एक बार अपने असली रूप में मेरे नाम से बनाए गए उस दल के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता हूँ, जो बजरंग के नाम को बदरंग कर रहे हैं।' कुछ देर बाद हम एक भव्य हाऊसिंग सोसायटी के बाहर पहुँचे तो दोपहर की तपती धूप में लम्बी क़तार देख कर

खड़े हो गए। पूछने पर पता चला कि दिन भर वॉट्सएप खेलने वाले उच्च मध्यम वर्ग के पैंशनयाफ्ता लोग सरकारी सब्सिडी पर मिलने वाले सस्ते टमाटर खरीदने के लिए खड़े हैं।

उन्होंने पूछा कि क्या ये टमाटर देश भर में सभी लोगों को मिल रहे हैं या केवल गोदी मीडिया में सरकार के कल्याणकारी कार्यों को दिखाने के लिए डंकाधानी में चुनिंदा स्थानों पर बेचे जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हर साल टमाटर समेत सभी सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं। फिर इस साल यह तमाशा क्यों? मैं बोला, 'प्रभु! चुनावी साल है। दस साल पहले महंगाई के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाली भाजपा अब विपक्ष के हमलों से पस्त होकर सब्सिडी पर टमाटर बेच रही है। अब तक विपक्ष शांत था। लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मन्दिर में नए-पुराने भगवानों की स्थापना के लिए अगले साल चुनाव होने हैं। इसलिए विपक्ष हमलावर है और सरकार सब्सिडी पर टमाटर बेच कर कल्याणकारी होने का सबूत दे रही है।'

पीए सिद्धार्थ

मासूम कलियों को रौंदने से बचाना होगा

अगर समाज का हर आदमी जागरूक हो जाएगा, तभी बालिकाओं को बचाया जा सकता है और तभी ऐसे बालिका दिवस सार्थक होंगे। अगर अब भी लापरवाही बरती तो एक दिन बालिकाओं का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर पछताने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। विश्व के देशों को इस विकराल हो रही समस्या पर लगाम लगाने के लिए विचार करना होगा'

बेशक 24 सितंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया, मगर ऐसे आयोजन केवल मात्र औपचारिकता भर रह गए हैं। केवल एक दिन पूरे विश्व में बालिकाओं की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, उसके बाद 364 दिनों तक मासूम कलियों को रौंदा जाता है। समूचे विश्व में बालिका दिवस पर भाषण प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, सेमिनार लगाए जाते हैं, कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, मगर सुधार शून्य ही रहता है। अगर सही मायनों में बालिकाओं को सुरक्षित बनाना है तो समाज के हर वर्ग को इसमें सहयोग देना होगा। तभी ऐसे आयेजन सफल हो सकते हैं, अन्यथा सुधार संभव नहीं हो सकता। आज पूरे विश्व में बालिकाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। आज भले ही मानव 21वीं सदी में पहुंच चुका है मगर उसकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। इतिहास गवाह है कि देश में लड़कियों ने शिक्षा, राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में सफलता की इबारतें लिखी हैं। समाज में बालिकाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, मासूम कलियों की हत्याएं की जा रही हैं। कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लिंग अनुपात घटता जा रहा है। मंदिरों, झाड़ियों में नवजात शिशु फैंके जा रहे हैं जिनमें अधिकांश लड़कियां होती हैं। समाज किस ओर जा रहा है, वह यह क्यों नहीं सोचता कि जिसने उसे जन्म दिया, वह भी एक लड़की ही थी।

कन्या भूरण हत्या के लिए समाज जिम्मेवार है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम चमका रही हैं, हर शिखर पर परचम लहरा रही हैं। आज धरती से लेकर आकाश तक बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर समाज को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज बेटियां एवरेस्ट पर्वत पर पहुंच रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। वंश परंपरा की खातिर कोख में ही कत्ल किए जा रहे हैं। आज सरकारों द्वारा बेटी है अनमोल जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। मगर कुछ तथाकथित दकियानूसी सोच रखने वाले लोगों के कारण ऐसे कार्यक्रमों पर बट्टा लग रहा है। जो लडक़े की चाहत में ऐसे घिनौने कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कसाई कहना चाहिए, जो जानबूझकर ऐसे रूह कंपा देने वाले कार्यों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। समाज को ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए जो लड़कियों के जन्म पर मातम मनाते हैं। समाज के लोग गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं, क्योंकि समाज में कोई इन घटनाओं को रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो इस पर रोक लग सकती है। आज भारत में ऐसे मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज का अभिशाप बनती जा रही हैं। कन्या भूरण हत्या एक अपराध है, मगर लोग निडर होकर बच्चियों को कूड़ेदानों व सुनसान जगहों पर फैंक रहे हैं। यह पतन की पराकाष्ठा है। अगर समय रहते इन घिनौने कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाला कल बहुत ही विनाशकारी होगा। ऐसी वारदातों से समाज का अहित होता है। यह चिंता का विषय बनता जा रहा है।

समाज के बुद्धिजीवियों को बालिकाओं को बचाने के लिए चिंतन करना चाहिए। बेटा-बेटी के अन्तर को खत्म करना होगा। अगर हर मां-बाप यह सोच रखे कि उसकी जो भी संतान होगी, चाहे लडक़ा हो या लडक़ी, उसका कत्ल नहीं किया जाएगा, तो लिंग अनुपात में सुधार हो सकता है। मगर समाज के लोगों को यह बात कौन समझाएगा, लोग अपनी मनमानी करते हैं। अगर समाज के लोग सक्रिय हो जाएं तो उन लोगों पर नजर रखी जा सकती है जो लिंग जांच करवाने के बाद बेटियों का बेरहमी से कत्ल करवाते हैं। समय-समय पर देश के राज्यों से ऐसे समाचार आते रहते हैं। ऐसे क्लिनिक चलाने वाले डाक्टरों को सजा-ए-मौत देनी चाहिए जो ऐसे नीच काम करते हैं। ऐसे लोगों को जल्लाद कहना गलत नहीं होगा, जो जानबूझकर अजन्मी कन्याओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं। समाज में गरीब लोग मेहनत-मजदूरी करके अपनी बच्चियों का पालन-पोषण कर रहे हैं, ऐसे घिनौने कार्यों को सरमाएदार लोग ही अंजाम देते हैं क्योंकि अमीर लोगों पर कोई उंगली नहीं उठाता। बेटियों को कोख में ही खत्म करवाने वाले राक्षसों को सूली पर टांगना चाहिए। समाज के यही तथाकथित अमीर लोग नवरात्रों में कंजकों को पूजते हैं, मगर एक दिन पूजा करके इनके पाप नहीं धुल सकते, क्योंकि इनके पापों की सजा खुदा जरूर देगा। महिलाओं को भी इसको रोकने के लिए आगे आना होगा। ऐसे लोगों को सजा दिलवानी होगी। अगर महिलाएं इसके विरुद्ध खड़ी हो जाएं तो इन पर पूर्ण रूप से रोक लग सकती है। मगर वंश परंपरा के कारण कई महिलाएं भी दोषी हैं। केन्द्र सरकार को इन मामलों पर संज्ञान लेना होगा। आज की बालिका कल की स्त्री है, उसके बगैर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज को जागरूक करने के लिए सरकार को संचार माध्यमों से अभियान चलाना होगा, ताकि लोगों को जागृत किया जा सके।

प्रत्येक शहर व गांव में शिविर लगाने चाहिए। अगर यह सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर चलता रहा तो आने वाला समय इतना भयंकर हो जाएगा कि अराजकता फैल जाएगी, जब चारों तरफ बालिकाओं का चीरहरण होगा। अगर समाज का हर आदमी जागरूक हो जाएगा, तभी बालिकाओं को बचाया जा सकता है और तभी ऐसे बालिका दिवस सार्थक होंगे। अगर अब भी लापरवाही बरती तो एक दिन बालिकाओं का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर पछताने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। विश्व के देशों को इस विकराल हो रही समस्या पर लगाम लगाने के लिए सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करना होगा। यह समय जागने का है। आओ, हम सब एकजुट होकर बालिकाओं को बचाने का संकल्प लें। बालिकाओं को बचाना हर भारतवासी का नैतिक कर्त्तव्य है, तभी ऐसे दिवसों की सार्थकता होगी।

30 सिंतबर तक एलआईसी के इस प्लान में कर सकते हैं निवेश, चूक गए तो नहीं होगी आपकी 'धन वृद्धि'

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की यह पॉलिसी 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस पॉलिसी का नाम एलआईसी धन वृद्धि है। यह एक एकल प्रीमियम पॉलिसी है जो पॉलिसीधारकों को गारंटीशुदा रिटर्न देती है। आपको इस पॉलिसी में केवल एक बार ही निवेश करना है जिसके बाद आपको आजीवन इस योजना का लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक पॉलिसी 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। इस पॉलिसी का नाम एलआईसी धन वृद्धि (LIC Dhan Vriddhi) है। यह एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है जो पॉलिसीधारकों को गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करती है। एलआईसी ने इस योजना की शुरुआत वित्तीय सुरक्षा और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो अब आपके पास सिर्फ चार दिन का ही समय बचा है। चलिए जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में।

सिंगल प्रीमियम है योजना

एलआईसी ने यह स्कीम 23 जून, 2023 को शुरू की थी जो अब जल्द ही समाप्त होने जा रही है। एलआईसी धन वृद्धि के लिए पॉलिसी अवधि 10 वर्ष निर्धारित है। यह योजना सिंगल प्रीमियम प्लान है मतलब आपको पॉलिसी में केवल एक बार पैसा निवेश करना होगा और फिर आप जीवन भर इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।

यूजर्स को इस पॉलिसी में जीवन सुरक्षा और बचत दोनों से लाभ होता है। इसके अलावा, निवेशक किसी भी समय इस योजना को रद्द कर सकते हैं।

पॉलिसी पर मिलता है लोन

इस पॉलिसी में पॉलिसीधारकों को लोन की भी सुविधा दी जाती है। आप प्लान लेने के 3 महीने पूरे होने के बाद में लोन का फायदा ले सकते हैं।

धन वृद्धि पॉलिसी की कुछ मुख्य बातें

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि पूरी होने से पहले पॉलिसी सरेंडर करना चाहता है, तो कुछ नियमों और शर्तों के अधीन सरेंडर मूल्य का भुगतान किया जाता है।

यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो इस प्लान के प्रावधान के तहत पॉलिसीधारक के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है।

परिपक्वता अवधि पूरी होने पर पॉलिसीधारक को गारंटीशुदा रिटर्न मिलता है।

यह योजना 10, 15 और 18 सालों की अवधि के लिए उपलब्ध है।

आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन या फिर एलआईसी एजेंट या एलआईसी के किसी भी ब्रांच के माध्यम से ऑफलाइन में भी खरीद सकते हैं।

सेबी ने फिर बढ़ाई डीमेट अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ने की आखिरी तारीख, अब 31 दिसंबर तक का है समय

सेबी ने डीमैट खातों में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है। ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनी विकल्प की बुकिंग को भी वैकल्पिक बना दिया है।

नई दिल्ली। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी के जोड़ने की आखिरी तारीख को सेबी ने आज आगे बढ़ा दिया है। सेबी ने मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने या फिर नॉमिनी को ना रखने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक करने की घोषणा की है।

इसके अलावा, व्यापार करने में आसानी हो इसलिए सेबी ने ट्रेडिंग खातों के लिए 'नॉमिनी का विकल्प' प्रस्तुत करना ऑप्शनल बना दिया गया है।

सेबी क्यों करवाना चाहता है नॉमिनी को एड?

सेबी ने इससे पहले मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक तय की थी। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि

डीमैट खातों के संबंध में, 'नॉमिनी की पसंद' जमा करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

ऑफलाइन निवेशकों के लिए सेबी ने दिया ये नोटिस

इसके अलावा, सेबी ने ऑफलाइन निवेशकों को पैन, नॉमिनी, फोन नंबर, बैंक खाते की डिटेल और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

2021 से बढ़ती आ रही है डेडलाइन

सेबी ने जुलाई 2021 में सभी मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नॉमिनी का विकल्प प्रदान करने के लिए कहा था जिसे फिर बाद में एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक और फिर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया गया था।

क्या होता है नॉमिनी?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे डीमैट अकाउंट धारक अपने मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति को नाम करना चाहता है। यह व्यक्ति आपके पिता, माता, पति या पत्नि, भाई-बहन, बच्चे या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है।

एक नाबालिग को भी नॉमिनी व्यक्ति के रूप में जोड़ा जा सकता है लेकिन इस स्थिति में नाबालिग के अभिवावक का भी डिटेल देना जरूरी होता है।

इनसाइड

घर खर्च के साथ आप भी कर सकती हैं अच्छी खासी बचत, फॉलो करें ये आसान टिप्स

आज के समय कमाने के साथ-साथ सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम सही समय पर पैसे सेव नहीं करते हैं तो हमें भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज हम कामकाजी महिला के साथ घरेलू महिलाओं को भी बताएंगे कि वो किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकती है।

नई दिल्ली। हर महिला कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करें। कई महिला पैसे सेव करने की कोशिश तो करती है पर उनसे पैसे सेव नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी पैसे सेव करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते जिसकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। हमारे पास जब एक लक्ष्य होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर पाते हैं। ऐसे में आप भी एक फाइनेंशियल गोल बना सकते हैं। यह गोल आपके रिटायरमेंट के बाद की इनकम का हो सकता है या फिर कहीं घूमने को लेकर भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आपको लद्दाख जाना है तो आप उसके लिए अभी से पैसे सेव कर सकते हैं। आपको हर महीने का एक बजट बनाना चाहिए। जब देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें बजट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह घर के खर्चों को पूरा करने और पैसे की बचत करने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है।

ट्रेडिंग घंटों में बदलाव की तैयारी कर रहा है NSE, ट्रेडर्स को मिलेगा ये लाभ

शेयर बाजार का सूचकांक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अपने व्यापारिक घंटों को बदलने की योजना बना रहा है। एनएसई इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग घंटे धीरे-धीरे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार एनएसई के इस कदम से संभावित रूप से रातोंरात जोखिम कम हो जाएगा। जानिए वर्तमान में क्या है टाइमिंग और कितना होगा बदलाव।

नई दिल्ली: स्टॉक मार्केट के प्रमुख सूचकांकों में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), ट्रेडिंग घंटे में बदलाव करने की योजना बना रहा है।

एनएसई चरणबद्ध तरीके से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग घंटे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एनएसई का यह कदम वैश्विक सूचना के बाद होने वाले रातोंरात जोखिम को संभावित रूप से कम कर देगा।

क्या होगा ट्रेडिंग टाइम?

समाचार एजेंसी पीटीआई को एनएसई के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने बताया कि एक्सचेंज सुबह 9.15 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक नियमित सत्र की समाप्ति के बाद शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सत्र की योजना बना रहा है।

श्रीराम कृष्णन ने बताया कि शाम के सत्र में लेनदेन को अगले कारोबारी दिन के कारोबारी सत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 बजे तक के ट्रेडिंग सेशन पर आने वाली प्रतिक्रिया के बाद, कमोडिटी डेरिवेटिव की तर्ज पर बाजार समय को रात 11.55 बजे तक धीरे-धीरे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।

खुदरा निवेशकों को मिलेगी मदद

एनएसई द्वारा प्रस्तावित उपाय से बाजार सहभागियों और खुदरा निवेशकों को मदद मिलेगी। वर्तमान में इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव बाजार दोपहर 3.30 बजे बंद हो जाते हैं जब अधिकांश यूरोपीय इक्विटी बाजार कारोबार के लिए खुल चुके होते हैं वहीं अमेरिकी इक्विटी बाजार बंद हो जाते हैं।

इंडियन ट्रेडर्स को होगा लाभ

एनएसई द्वारा इस प्रस्ताव से व्यापारिक घंटों को बढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय व्यापारियों को वैश्विक घटनाओं पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करना है।

इसके अलावा, लंबे सत्रों से ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ावा मिलने और मालिकाना डेस्क और हेज फंड सहित महत्वपूर्ण व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की उम्मीद है, जो गिफ्ट सिटी जैसे प्रतिस्पर्धियों में शिफ्ट हो रहे हैं, जहां चौबीसों घंटे ट्रेडिंग होता है।

सेबी ने 2018 में दी थी ये अनुमति

2018 में, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में अपने ट्रेडिंग घंटे सुबह 9 बजे से रात 11.50 बजे के बीच निर्धारित करने की अनुमति दी थी जो कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग घंटों के समान था। वर्तमान में कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट सुबह 10 बजे से रात 11.55 बजे के बीच निर्धारित है।

म्यूचुअल फंड में सिप या लंपसंप क्या है निवेश करने का सही तरीका, समझें दोनों के फायदे और नुकसान

Mutual Funds में एसआईपी या लंपसम कैसे निवेश करना चाहिए। इसके लेकर निवेशकों के मन में कन्फ्यूजन बना रहता है। निवेशक को किसी भी स्कीम का चुनाव करने के पहले अपनी निवेश अवधि को चुनना चाहिए। एसआईपी के जरिए निवेश से बाजार के सभी टाइमफ्रेम का फायदा निवेशक को मिल जाता है। लंपसम में आप बाजार की गिरावट का फायदा उठा सकते हैं।

नई दिल्ली। आज के समय में निवेश के काफी सारे विकल्प हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर है। इसमें कोई भी व्यक्ति लंपसम और एसआईपी के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि दोनों में से सबसे बेहतर विकल्प कौन-सा है। एसआईपी और लंपसम दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं।

SIP के जरिए निवेश फायदे

एसआईपी के जरिए निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें बाजार के सभी टाइमफ्रेम का फायदा निवेशक को मिल जाता है। ये एक तरह से ईएमआई की तरह से होता है। हर महीने एक किस्त के रूप में निर्धारित राशि म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर दी जाती है। लंबी अवधि में निवेश के लिए एसआईपी एक अच्छा विकल्प है। इससे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है।

नुकसान

एसआईपी केवल लंबी अवधि के निवेश के लिए अधिक प्रभावी होता है। म्युचूअल फंड स्कीम में एक निश्चित तारीख को ही एसआईपी जाती है। कई बार देरी होने पर जुर्माना आदि भी भरना पड़ता है। ज्यादातर देखा गया है कि एसआईपी केवल फिक्स इनकम वाले लोगों के लिए अच्छी रहती है।

Lumpsum निवेश फायदे

लंपसम निवेश का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आप बाजार की परिस्थिति के मुताबिक निवेश कर सकते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए एक बड़ा निवेश करना चाहते हैं और आपकी आय अस्थिर है तो भी लंपसम एक अच्छा तरीका हो सकता है।

उदाहरण के लिए कोरोना के समय जब बाजार में बड़ी गिरावट आई तो म्युचूअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश एक अच्छा मौका था।

नुकसान

लंपसम में निवेश करने का नुकसान यह है कि आप बाजार के सभी टाइमफ्रेम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है।

मुकेश अंबानी के बाद आकाश, ईशा और अनंत भी नहीं लेगें RIL से सैलरी, कंपनी की बोर्ड बैठक में हुआ फैसला

RIL की बोर्ड बैठक के दौरान हुए फैसले में कहा गया है कि आकाश ईशा और अनंत को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने खुद 2020-21 वित्तीय वर्ष के बाद से कंपनी से वेतन नहीं लिया है।

नई दिल्ली। Reliance Industries Ltd ने कंपनी के बोर्ड में मुकेश अंबानी के तीन बच्चों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, RIL के एक प्रस्ताव के अनुसार, आकाश, ईशा और अनंत को केवल बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए फीस मिलेगी। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

अंबानी के तीनों बच्चों को नहीं मिलेगी सैलरी

RIL की बोर्ड बैठक के दौरान हुए फैसले में कहा गया है कि आकाश, ईशा और अनंत को वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने खुद 2020-21 वित्तीय वर्ष के बाद से कंपनी से वेतन नहीं लिया है। इसके विपरीत, उनके चचेरे भाई निखिल और हितल सहित अन्य कार्यकारी निदेशकों को वेतन, अनुलाभ, भत्ते और कमीशन का एक संयोजन मिलता है। अंबानी के बच्चों को उनकी पत्नी नीता की तरह है पैसे मिलेंगे, जो 2014 में कंपनी के बोर्ड में शामिल हुई हैं।

नीता अंबानी ने ली इतनी फीस

कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, नीता ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान 6 लाख रुपये की सिटिंग फीस और 2 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया है। कंपनी की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक के दौरान हाल ही में एक घोषणा में, मुकेश अंबानी ने अपने तीन बच्चों को रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) में शामिल करने की पुष्टि की।

उन्होंने अगली पीढ़ी के लीडर्स को सलाह देने और सशक्त बनाने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ अगले पांच वर्षों तक कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है।

शेयर धारकों से मांगी अनुमति

रिलायंस ने बोर्ड निदेशक के रूप में आकाश, ईशा और अनंत की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए एक डाक मतपत्र शुरू किया है। शेयरधारकों को भेजे गए नोटिस के अनुसार, उनके पारिश्रमिक में बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए व्यय प्रतिपूर्ति और लाभ से संबंधित कमीशन शामिल होंगे।

मुकेश अंबानी ने शुरुआत में 2022 में समूह के लिए उत्तराधिकार योजना की शुरुआत की है, जिसमें उनके तीन बच्चों में से प्रत्येक ने कंपनी के भीतर विभिन्न प्रभागों का प्रभार संभाला है।

सिरदर्द को 5 मिनट में ठीक करने वाली प्राकृतिक चिकित्सा

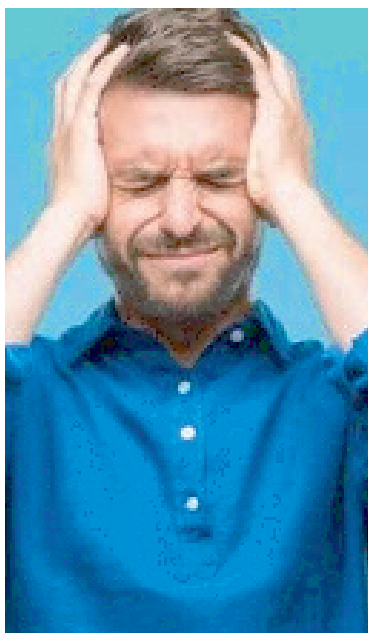

नाक के दो हिस्से हैं दायाँ स्वर और बायां स्वर जिससे हम सांस लेते और छोड़ते हैं ,पर यह बिल्कुल अलग - अलग असर डालते हैं और आप फर्क महसूस कर सकते हैं। दाहिना नासिका छिद्र ₹सूर्य₹ और बायां नासिका छिद्र ₹चन्द्र₹ के लक्षण को दर्शाता है या प्रतिनिधित्व करता है।

सरदर्द के दौरान, दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से सांस लें और बस ! पांच मिनट में आपका सरदर्द ₹गायब₹ है ना आसान ?? और यकीन मानिए यह उतना ही प्रभावकारी भी है।

अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो बस इसका उल्टा करें यानि बायीं नासिका छिद्र को बंद करें और दायें से सांस लें, और बस ! थोड़ी ही देर में ₹तरोताजा₹ महसूस करें।

दाहिना नासिका छिद्र गर्म प्रकृति रखता है और बायां ₹ठंडी प्रकृति

अधिकांश महिलाएं बाएं और पुरुष दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेते हैं और तदन रूप क्रमशः ठन्डे और गर्म प्रकृति के होते हैं सूर्य और चन्द्रमा की तरह।

प्रातः काल में उठते समय अगर आप बायीं नासिका छिद्र से सांस लेने में बेहतर महसूस कर रहे हैं तो आपको थकान जैसा महसूस होगा ,तो बस बायीं नासिका छिद्र को बंद करें, दायीं से सांस लेने का प्रयास करें और तरोताजा हो जाएँ।

अगर आप प्रायः सरदर्द से परेशान रहते हैं तो इसे आजमायें ,दाहिने को बंद कर बायीं नासिका छिद्र से सांस लें बस इसे नियमित रूप से एक महिना करें और स्वास्थ्य लाभ लें।

बस इन्हें आजमाइए और बिना दवाओं के स्वस्थ महसूस करें।

10 लाख का कर्ज लो और 5 ही वापस करो , बाकी बिहार सरकार भरेगी

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो बिहार सरकार ने शुरू की है और इसके तहत अल्पसंख्यकों को उद्योग के लिए सरकार 10 लाख का कर्ज देगी और वापसी 5 लाख ही लेगी बाकी सरकार खुद भरेगी... क्या इसे मुस्लिम तुष्टिकरण कहना गलत है ? बाकी हिंदुओं को क्या मिला ? क्या हिंदू केवल Tax भरने के लिए हैं ?

नीतीश बाबू ने सिद्ध कर ही दिया की वो मुसलमानों के सच्चे रहनुमा है, और खोल दी खजाने की चावी। हिंदुओं का क्या है उन्हें तो जाति में बांट तो फिर जीतेगा कौन जिसे मुसलमानों के वोट मिलेंगे, यानी जाति में बंटे हिंदू की कोई कीमत कीमत तो केवल संगठित मुस्लिम वोट की है इसलिए उनको खुशियों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, और वही नीतीश जी कर रहे हैं इसमें उनकी क्या गलती ? गलती जिसकी है (हिंदू) वो सोचें कि बंटे रहना है या संगठित होकर एक मजबूत भारत का निर्माण करना है ताकि हमारी पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बने..

बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार देने के नाम पर एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसमें से केवल 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। शेष 5 लाख रुपए बिहार सरकार अनुदान के तौर पर देगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 10 लाख के कर्ज में से 5 लाख रुपए राज्य सरकार माफ कर देगी। इस योजना को 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना' नाम दिया गया है। राज्य सरकार ने इसे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा उद्यमी योजना का विस्तार बताया

है। भले बिहार सरकार इस योजना को अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार मुहैया कराने का प्रयास बता रही है। भले इसे समाज के अन्य वर्गों के लिए चली आ रही योजना का विस्तार बता रही है। लेकिन जिस समय पर बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है, इसे तुष्टिकरण की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार उस राजद के भरोसे चल रही है जो खुलकर माय (मुस्लिम+यादव) समीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी से अलग होने के बाद से नीतीश कुमार भी खुद को मुस्लिमों को सच्चा रहनुमा बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

'बेरोजगारी कम करना चाहती है सरकार'

बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने इस योजना के लेकर कहा है कि राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों-महिलाओं के बीच बेरोजगारी कम करने और उन्हें स्वरोजगार की तरफ बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना यानी एमएयूवाई है। बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क करना होगा। इसके तहत मामूली दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा।

गौरतलब है कि बिहार सरकार मुस्लिमों को ध्यान में रखकर कई योजनाएँ बना चुकी है। इसी साल जुलाई में नीतीश कुमार की सरकार ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एकमुश्त 25 हजार रुपए मदद देने की घोषणा की थी। योजना का लाभ 18 से 50 साल तक की महिलाओं को मिलेगा

राशन डीलर 1 नवम्बर सेअनिश्चितकालीन राशन वितरण बंद की चेतावनी

राशन डिलरों को कमीशन देने की मांग कमीशन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा, भीलवाडा। ऑल इंण्डिया फेयर प्राईस शॉप डिलर फैडरेशन जिला भीलवाडा के जिलाध्यक्ष संजय तिवाडी ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि राशन डिलरों द्वारा वर्ष 2020 में आईसीडीएस की पोषाहार वितरित की गयी जिसका कमीशन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिलने एवं पीडीएस के अन्तर्गत निरन्तर सामग्री वितरित की जा रही है जिसका कमीशन अप्रेल 2023 से सितम्बर 2023 तक का यानि की 6 माह से आज दिनांक तक नहीं मिलने सहित राज्य सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण करवाया जा रहा है जिसके 10 रू प्रति पैकेट के कमीशन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 15 अगस्त 2023 को करने उपरांत भी कमीशन जारी नहीं करने से राशन डिलरों को आर्थिक संकट झेलना पड रहा है। जिलाध्यक्ष तिवाडी ने ज्ञापन में 6 माह का कमीशन एक साथ देने व लम्बित सभी कमीशन 31 अक्टूबर 2023 तक नही देने पर 1 नवम्बर 2023 से अनिश्चित कालीन राशन वितरण बंद करने की चेतावनी दी है। इस दौरान अशोक लोढ़ा, मुश्ताक अहमद शेख, महावीर मेहता, महावीर राठी, संजय खटीक, राजमल टेलर, प्रेमशंकर जाट आदि उपस्थित थे।

कैपिटल हॉस्पिटल की घातक शिकायतः बेटे ने दी बेटी !

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर : बोले बेटे ने लड़की दे दी. ऐसी शिकायतें भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल से आई हैं. पहले तो उन्होंने कहा कि लड़का पैदा हुआ है, फिर कहा कि लड़की हुई है. ऐसी शिकायत केंद्रपाड़ा जिले के राजकनिका इलाके के राणाकृष्ण बिस्वाल ने की है.

बताया गया कि कल रात साढ़े दस बजे एक लड़के का जन्म हुआ है। लेकिन फोटो खींचते वक्त उन्होंने देखा कि ये तो एक लड़की है. इसके लिए उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की. राणाकृष्ण ने कहा कि जब तक बच्चे की डीएनए जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक बच्चे को नहीं लिया जायेगा.

डिलीवरी के बाद नर्स ने बताया कि उसका बच्चा लड़का है। बच्चे के जन्म के समय उन्हें कन्यादान हुआ। शिकायत के बाद निदेशक ने घटना की जांच की जानकारी दी. निदेशक ने बताया कि इससे डीएनए टेस्ट किया जायेगा. राणाकृष्ण ने कहा, मेडिकल स्टाफ ने कहा कि मेरे बेटे का जन्म कल सुबह 10 बजे हुआ है. बाद में नर्स ने बच्चे को लाकर सास को दे दिया। जब बच्चे की फोटो ली गई तो पता चला कि वह लड़का नहीं बल्कि

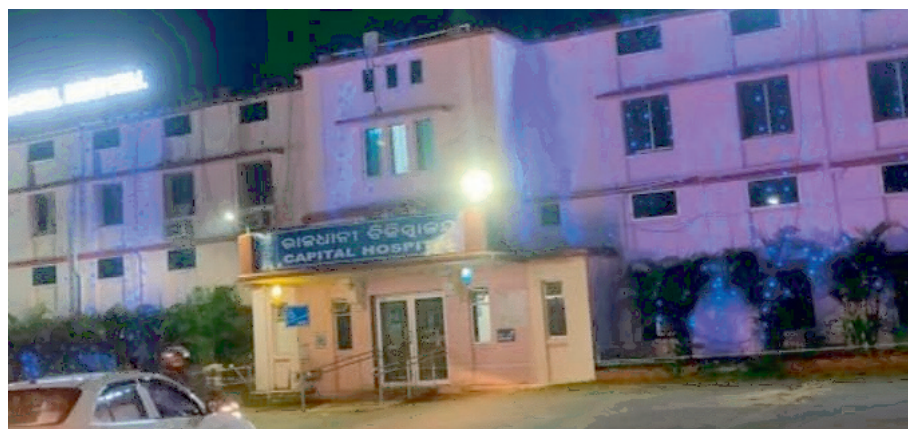

लड़की है।

तभी नर्स ने किसी से पूछा, मेरा बेटा है, लड़की ने क्या दिया, लेकिन वह बिना कुछ बताए भाग गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और बोले कि आपने बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि उनका एक दूसरे व्यक्ति का बेटा है.

उधर, निदेशक ने शिकायत के बाद घटना की जांच की जानकारी दी है. निदेशक ने बताया कि इससे डीएनए टेस्ट कराया जायेगा. उन्होंने कहा, अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम जांच करेगी. पुलिस डॉक्टर और नर्स से भी पूछताछ कर रही है।

नया समेलिया चारभुजा मंदिर पर लगाया छप्पन भोग

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। जलझूलनी एकादशी महापर्व पर नया समेलिया चारभुजा नाथ मंदिर पर विशाल शोभायात्रा व छप्पन भोग का आयोजन किया गया ।चारभुजा नाथ मंदिर के पुजारी लादू लाल वैष्णव ने बताया की मंदिर की स्थापना 20 जून 2011 को की गई, जिसके पश्चात पहली बार चारभुजा नाथ के छप्पन भोग का आयोजन किया गया जिसमें आसपास के गांवों के ग्रामीण व गांव के ग्रामीण महिलाएं व बच्चे बच्ची मौजूद रहे व भक्तों में काफी उत्साह का माहौल था।

अपने भीतर की बुराईयों का त्याग ही उत्तम त्याग धर्म- पं. विवेक शास्त्री

सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड में पयुर्षण पर्व का आठवां दिन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। सुपार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर हाऊसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर में पर्यूषण के आठवां दिन उत्तम त्याग धर्म पर बताते हुए पं. विवेक शास्त्री ने बताया कि निज शुद्धात्मा के ग्रहणपूर्वक परद्रव्यों में ममत्व, एकत्व रूप, मोह, राग, द्वेष रूप विकारी भावों का छोड़ना ही वास्तविक उत्तम त्याग धर्म है। निश्चय और व्यवहार मोह-राग-द्वेष को निश्चय त्याग व औषधि, शास्त्र, अभय और आहार आदि सुपात्रों को देना वह व्यवहार त्याग या दान है। त्याग का अर्थ है छोड़ना। परिग्रह का त्याग करना त्याग है, बाहरी परिग्रह को छोड़ देना बहिरंग त्याग है तथा अतरंग परिग्रह (विकार, बुराईयाँ आदि) छोड़ देना आंतरिक त्याग है। ग्रहण करते समय भी छोड़ने का भाव रहना उत्तम त्याग धर्म है।

अध्यक्ष राकेश पाटनी ने बताया कि मुख्य शांतिधारा एवं आरती पुण्यार्जक का सौभाग्य शांता देवी, विनीत कोठारी परिवार को मिला। आज प्रातः दशलक्षण मंडल विधान के अन्तर्गत उत्तम त्याग धर्म के अर्घ महापत्रोंद्वारा मण्डल विधान पर अर्पित गया। मीडिया प्रभारी भागचन्द पाटनी ने बताया कि मध्यान्ह में पं. विवेक शास्त्री के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र का वाचन, सामायिक, प्रतिक्रमण शास्त्र स्वाध्याय किया गया। सांयकाल की जिनेन्द्र-भगवान मंगल आरती मंगल 1008 दीपों के साथ महाआराधना की गयी। श्री महावीर दिगम्बर जैन सेवा समिति के तत्वाधान में म्युजिकल भजन संध्या का आयोजन किया गया।

85 की वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहब फाल्के

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत - गाइड, प्यासा, ,कागज के फूल, चौहदवीं का चांद और खामोशी जैसी 1955-60 की सुपर डुपर फिल्मों की अदाकारा को सालों बाद भारतीय सिनेमा में वहीदा रहमान के योगदान के लिए इस साल के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

इस बावत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक्स अकाउंट पर नोट सांझा किया है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा है कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान को पांच दशक से अधिक की अभिनय यात्रा में पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा रहमान जी ने एक भारतीय नारी के समर्पण और सामर्थ्य का उदाहरण पेश किया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे वक्त में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित किया गया है, तब वहीदा रहमान लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना गर्व की बात है। दिग्गज अदाकारा को यह सम्मान दिया जाना वास्तव में हिंदी सिनेमा की महिलाओ के लिए एक ट्रिब्यूट सरीखा है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी वहीदा रहमान को उनके शानदार अभिनय और सिनेमा की दुनियां में योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जा चुका है। 85 वर्षीय अभिनेत्री वर्ष 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजी जा चुकीं है। साल 1994 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। साल 2001 में उन्हें (आईआईएफए) लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

संथारा साधिका श्री चरण प्रक्षा जी की पुण्यतिथि मनाई

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाडा। माधवनगर स्थित दिवाकर धाम पर संथारा साधिका महासती श्री चरण प्रज्ञा जी महाराज की पुण्यतिथि सामयिक साधना एवं नवकार मंत्र के जाप के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर श्री जैन दिवाकर चरण साधना सेवा संस्थान के मंत्री, दिवाकर महिला मण्डल की अध्यक्षा श्रीमति सुमित्रा बोथरा (सांखला) के सानिध्य में मनाई गई एवं उन्होंने महासती के जीवन पर प्रकाश डाला, महामंत्री सुनीता गांधी द्वारा महिला मण्डल की महिलाओं से प्रश्न पूछे गये। महासती की पुण्यतिथि मनाने हेतु चांदमल बोहरा, शांतिलाल बाबेल, पवन बाबेल, अशोक बोथरा, धर्मेन्द्र कोठारी, अनिल लोढ़ा, लक्ष्मीलाल कूकड़ा, विजय बोहरा, सुनीता कोठारी, सरोज लोढ़ा, सुशीला सिपानी, नीलम कांकरिया, मीना बुरड़, अलका झामड़, मधु चौधरी, मीरा बोहरा, सुनीता ओस्तवाल, रजनी बाफना, संतोष लोढ़ा आदि उपस्थित रही।

सांप का जहर दोगुनी तेजी से भरेगा घाव! आईआईटी जोधपुर ने खोजा जहर से अनोखा इलाज

परिवहन विशेष न्यूज

सांप के जहर में जो रोगाणुरोधी पेप्टाइड मौजूद है इसमें भिन्न हाइड्रोफोबिसिटी और चार्ज स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण यह बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है।सांप का जहर घावों के इलाज में होगा कारगर

आईआईटी जोधपुर में शोधकर्ताओं ने तैयार किया केमिकल कम्पाउंड

बैक्टीरियल रसिस्टेंस से भी लड़ सकता है यह केमिकल कम्पाउंड

सांप का जहर जख्मों के लिए बनेगा संजीवनी ! जी हां, आईआईटी जोधपुर में सांप के जहर से एक ऐसा केमिकल कम्पाउंड तैयार किया गया है जो घावों को बहुत जल्दी ठीक कर देगी। इसके बारे में कहा गया है यह सर्जरी के बाद रह जाने वाले घावों को भी कहीं ज्यादा तेजी से ठीक कर देगा। मेडिकल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह रोगाणुरोधी पेप्टाइड है जो घावों को जल्दी से भरने में मदद करेगा।

आईआईटी जोधपुर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोइंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्टहेल्थकेयर में प्रोफेसर सुरजीत घोष ने कहा कि सांप के जहर में जो नुकसानदेही तत्व होता है, उसे हटाकर सिर्फ इसके रोगाणुरोधी गुणों को इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने एक छोटा हेलिकल पेप्टाइड इसके एन-टर्मिनस पर जोड़ा है ताकि यह कम्पाउंड आसानी से रोगाणु की कोशिश में प्रवेश कर जाए और उसे खत्म कर दे। गौरतलब है कि बढ़ते एंटी बायोटिक इस्तेमाल से अब बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं में दवाइयों के प्रति रसिस्टेंस का खतरा पैदा हो गया है। मेडिकल क्षेत्र के वैज्ञानिक इसे लेकर चिंता में हैं, क्योंकि इससे दवाइयों का असर होना बंद हो जाएगा, और रोगों का इलाज करने में कठिनाई होने लगेगी।

सांप के जहर में जो रोगाणुरोधी पेप्टाइड मौजूद है इसमें भिन्न हाइड्रोफोबिसिटी और चार्ज स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण यह बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। इनकी क्षमता बहुत अधिक बताई गई है लेकिन मनुष्यों के लिए इसका इस्तेमाल एक सीमा तक ही किया जा सकता है। इस शोध से अब दो चीजों का समाधान बहुत आसानी से

हो सकेगा। पहला ये कि इसमें एक मेम्ब्रेन बनाने वाली क्षमता पाई जाती है जिसके कारण बैक्टिरिया इसके खिलाफ रसिस्टेंस पैदा नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसे इंफेक्शन को हटाने वाले पदार्थ की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह खुद भी कारगर होगा, साथ ही इसे दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

शोध डॉक्टर सुरजीत घोष व उनके सहयोगियों, प्रोफेसर डॉ साम्या सेन, रामकमल समत, डॉ मौमिता जश, सत्यजीत घोष, राजशेखर रॉय, नबनिता मुखर्जी, सुरोजीत घोष और डॉ जयिता सरकार द्वारा किया गया है। जानकारी के अनुसार इसे जर्नल आफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959 .
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985 . DCP Licensing Number F .2 (P-2)